मध्यप्रदेश वनांचल संदेश

जनवरी–जून 2022

RNI Reference No.: 1322876 Title Code : MPHIN34795 Year : 5 Edition 20 & 21

केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमीत शाह जी द्वारा भोपाल में आयोजित वन समिति सम्मेलन में हितग्राहियों को लाभांश वितरण - दिनांक 22/04/2022

Devraj Dharmik

मध्यप्रदेश वनांचल संदेश

जनवरी - जून 2022

Patron :

Ramesh Kumar Gupta
Principal Chief Conservator of Forests
and Head of Forest Force Satpura Bhawan, Bhopal

Editorial Board :

Atul Kumar Jain
Principal Chief Conservator of Forests
(Research, Extension and Lok Vaniki)

Chitranjan Tyagi
Principal Chief Conservator of Forests
(Development/ JFM)

Bhagwat SIngh
Additional Principal Chief Conservator of Forests
(M.P. State Minor Forest Produce Trading &
Development Co-operative Federation)

Ramesh Kumar Shrivastav
Principal Chief Conservator of Forests
(IT & CEO CAMPA)

H.S. Negi
Additional Principal Chief Conservator of Forests
(Wildlife)

S.P. Sharma
Additional Principal Chief Conservator of Forests
(Green India Mission)

Capt. Anil Kumar Khare
Additional Principal Chief Conservator of Forests
(Madhya Pradesh Rajya Van Vikas Nigam Limited)

H.C. Gupta
Chief Conservator of Forests (Social Forestry, Bhopal)

Alvin Burman
DCF (Research, Extension and Lok Vaniki)

B.K. Dhar
Prachar Adhikari (Samanvay)

Editor :

Dr. U. K. Subuddhi
Additional Principal Chief Conservator of Forests
(Research, Extension and Lokvaniki) Bhopal

Prachar Prasar Prakosth Team :

Deepak Meshram
Gaurav Rajput

Owner & Publisher :
Prachar Prasar Prakosth (M.P.F.D.)
Printed by Madhya Pradesh Madhyam, Bhopal

Contact :
Prachar Prasar Prakosth, Room No. 140,
Satpura Bhawan, Bhopal
Email : dcfpracharprasar@mp.gov.in
Contact : 0755-2524239

वनांचल संदेश

क्र.	विषय	पृष्ठ क्र.
1	मध्यप्रदेश में वानिकी विकास के बढ़ते चरण	1
2	वन समितियों के लाभांश में वृद्धि : वन समिति सम्मेलन, भोपाल	7
3	वन एवं वन्यजीव संरक्षण जागरूकता अभियान : वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	11
4	सरलीकृत हुई संग्रहित लघु वनोपज की निर्वर्तन प्रक्रिया	14
5	डॉ. कुँवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री, वन, म.प्र. शासन द्वारा : वन विहार राष्ट्रीय उद्यान-जू में वाईल्ड केफे का पुन: शुभारंभ	15
6	प्रथम पक्षी सर्वेक्षण : पेंच टाइगर	16
7	मन्धान जलग्रहण क्षेत्र उपचार परियोजना से क्षेत्र का समग्र विकास	18
8	म.प्र. राज्य बांस मिशन द्वारा वन-कर्मियों को बांस के तकनीकी विशेषज्ञ बनाने हेतु प्रशिक्षण	21
9	Earth Hour day Awareness Program - 2022	24
10	विश्व पर्यावरण दिवस पर वन विभाग द्वारा राज्य में आयोजित विभिन्न गतिविधियां	25
11	“एक जिला, एक उत्पाद ” : बांस, वन वृत्त, रीवा	30
12	म.प्र. राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ एवं एम.एफ.पी- पार्क : स्कॉच सिल्वर अवॉर्ड 2022 से सम्मानित	32
13	अखिल भारतीय बाघ आंकलन-2022	33
14	73वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन	34
15	‘Collarwali Supermom’ the legendary tigress of Pench Tiger Riserve	36
16	शहरी क्षेत्र में वृक्षारोपण की दिशा में एक सफल प्रयास	39
17	जनजातीय कौशल विकास क्षेत्र में कान्हा प्रबंधन की नई पहल	42
18	विश्व गोरैया दिवस जागरूकता कार्यक्रम - 2022	43
19	बांस मिशन की कार्यशाला : क्षेत्रीय वनमण्डल, देवास	44
20	रोपणी बांसापुर वन विस्तार इकाई सीहोर सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल	46
21	‘Vulture Telemetry Project’ “Satellite Tracking of Vultures in Panna Tiger Reserve”	49
22	अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस-2022	54
23	अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस पर पुरस्कारों का वितरण	57
24	वनांचल संदेश पत्रिका माह “अक्टूबर - दिसम्बर 2021” का विमोचन	60
25	क्या आप जानते हैं ?	61
26	कविता : कभी सागौन लेकर के.....!	62
27	भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति	63
28	वानिकी गतिविधियां कार्टूनिस्ट की नजर में	66
29	अखबारों के आइने में	67

संदेश

वन विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका- "म.प्र. वनांचल संदेश" से विभागीय गतिविधियों तथा क्षेत्रीय वन इकाइयों द्वारा किये जा रहे अभिनव प्रयासों की तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त होती है। इसका लाभ प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में लिया जा सकता है। वन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये यह प्रकाशन अत्यंत उपयोगी होता जा रहा है।

मध्यप्रदेश वनांचल संदेश के जनवरी से जून 2022 के संयुक्त अंक में वन विकास एवम् वनसंरक्षण के साथ ही वन्यप्राणी प्रबंधन के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयासों को छायाचित्रों के माध्यम से रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है।इस सराहनीय प्रयास के लिये पत्रिका का सम्पादक मण्डल तथा प्रकाशन कार्य में संलग्न अमला बधाई के पात्र हैं।

आशा है कि विभाग की गतिविधियों को जनसाधारण तक पहुँचाने में वनांचल संदेश का यह अंक सफल होगा।

शुभकामनाओं सहित,

रमेश कुमार गुप्ता

प्रधानमुख्य वनसंरक्षक
वन बल प्रमुख

संदेश

प्रदेश में वन विभाग द्वारा वनों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में प्रभावी पहल हुई है, जिसका लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। वन तथा प्रकृति के प्रति जनचेतना जागृत करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण कार्य तथा वन्यप्राणियों की सुरक्षा तथा महत्वता को बनाए रखने के कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।

इस अंक में जनवरी से जून माह 2022 में वनविभाग की विभिन्न गतिविधियों का उल्लेख किया जा रहा है, जिनमें वानिकी विकास के बढ़ते कदम, वनसमितियों का सम्मेलन, वन एवं वन्य जीव संरक्षण जागरूकता अभियान, वन समितियों की सफलता का उल्लेख, विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित विभिन्न गतिविधियां आदि वन एवं वन्यजीव संरक्षण एवं संवर्धन में प्रमुख प्रेरणादायक स्त्रोत के रूप में प्रस्तुत हैं।

आशा है कि, प्रदेश को हरा-भरा बनाये रखने में तथा वन्यजीवों के संरक्षण में वन विभाग के सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संगठन, जनसामान्य के साथ मिलकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और सक्रियता के साथ करते रहेंगे।

अतुल कुमार जैन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी
म.प्र. भोपाल

सम्पादकीय

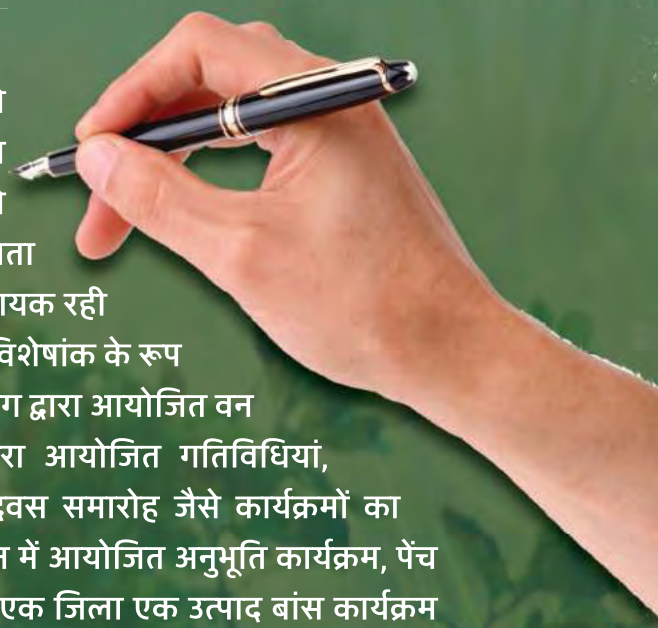

मध्यप्रदेश वनांचल संदेश हम सब की सकारात्मक भागीदारी से चलने वाला एक जीवंत संदेश वाहक है इसमें हम विभाग द्वारा किए गए कार्यों तथा शासन की जनकल्याण की योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत करते हैं विगत वनांचल संदेश की अपार सफलता इस अंक को अधिक रोचक तथा परिष्कृत बनाने के लिए प्रेरणादायक रही है। वनांचल संदेश का यह अंक जनवरी से जून 2022 छह माही विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। इस अंक में प्रदेश स्तर पर वन विभाग द्वारा आयोजित वन समिति सम्मेलन, विश्व पर्यावरण दिवस पर वन विभाग द्वारा आयोजित गतिविधियां, 73वें गणतंत्र दिवस समारोह तथा अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस समारोह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित अनुभूति कार्यक्रम, पेंच टाइगर रिजर्व में पक्षी सर्वेक्षण तथा बांस मिशन द्वारा आयोजित एक जिला एक उत्पाद बांस कार्यक्रम इस पत्रिका में नूतन प्रस्तुति देता है।

इस अंक में जहां एक ओर देश में पहली बार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान द्वारा vulture telementary project “satellite tracking of vulture” गिद्धों के संरक्षण की दिशा में नई पहल को दर्शाया गया है वहीं दूसरी ओर टाइग्रेस "कॉलरवाली सुपरमॉम" को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

आशा है कि प्रस्तुत अंक वन विभाग कि उल्लेखनीय गतिविधियों को जनसाधारण तक पहुंचाने, वनों, वन्यप्राणियों और वनवासी समुदायों के कल्याण की राह आसान बनाने में सफल साबित होगा।

शुभकामनाओं सहित।

डॉ. यू. के. सुबुद्धि

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी
म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश में वानिकी विकास के बढ़ते चरण

प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर मध्यप्रदेश में 94,689 वर्ग किलोमीटर वनक्षेत्र है, जो राज्य के भू-भाग का 30.72 प्रतिशत तथा देश के कुल वनक्षेत्र का लगभग 12.10 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश से निकली जीवनदायिनी नदियां प्रदेश के साथ-साथ चारों दिशाओं में पड़ोसी राज्यों के लिए जल का स्त्रोत हैं, इसीलिए मध्यप्रदेश को देश का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्यप्रदेश की नदियों में जल का स्त्रोत जलागम में स्थित वनावरण है, इसलिए प्रदेश का वन आवरण न केवल मध्यप्रदेश बल्कि संपूर्ण देश के विकास एवं सम्पन्नता के लिए महत्वपूर्ण है।

मध्यप्रदेश की वन नीति वर्ष 2005 में लागू की गई है। विभाग दो मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। वन तथा वन्यजीवों की सुरक्षा को प्राथमिकता में रखते हुए उनके संवर्धन के साथ ही वनों पर आश्रित ग्रामीणों के सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में प्रभावी पहल की गई है। ग्रामीण अंचलों में विकास गतिविधियों के संचालन करने वाले विकास विभागों में वन विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये की गई प्रभावी पहल का ही यह परिणाम है कि वनों के साथ-साथ इस पर आश्रित ग्रामीणों की स्थिति में भी सुधार हुआ है।

भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून द्वारा 2 वर्ष के अंतराल पर देश के वन आवरण का आंकलन किया जाता है। वर्ष 2005 से 2021 तक मध्यप्रदेश के वनावरण में 1480 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि में अति सघन वन के क्षेत्रफल में 2426 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। सभी तरह के मानव जनित दबावों के बावजूद वनों के क्षेत्रफल और गुणवत्ता में हुई यह वृद्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि में मध्यप्रदेश के नागरिकों विशेष तौर पर वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले वनवासी समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश - मध्यप्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश - रोडमैप 2023 के रूप में एक महत्वाकांक्षी पहल की है। इसे मूर्त रूप देने हेतु विभाग की चिन्हित गतिविधियों पर कार्ययोजना तैयार की जा रही है, इसके अंतर्गत बफर में सफर मुहिम के माध्यम से मानसून पर्यटन को बढ़ावा देना, टाइगर सफारी विकसित करना, लकड़ी/बांस के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन हेतु दो विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास, 20 बांस क्लस्टरों का व्यवस्थित विकास, प्रदेश की वनोपज का "मध्यप्रदेश उत्पाद" के रूप में जीआई टेगिंग, वनोपज के बेहतर मूल्य हेतु वनोपज मूल्य संवर्धन विकास, वन आधारित उद्यमों को प्रोत्साहन, प्रदेश में उपयुक्त हैबिटेट में चीतों को लाना, बाघों का घनत्व बढ़ाने और वन स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बाघों को अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में स्थानांतरण करना, वनों के बाहर वृक्ष आवरण बढ़ाने हेतु गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए पहल तथा भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर पारदर्शिता को बढ़ाने आदि के कार्य किये जाएंगे।

प्रदेश में बांस गुणवत्ता में सुधार और मूल्य संवर्धन के लिए 20 क्लस्टरों में बांस की विभिन्न प्रजातियों का रोपण पूर्ण हो चुका है। पन्ना आंवला तथा पातालकोट शहद की जीआई टेगिंग हेतु वैज्ञानिक अध्ययन कराया गया है। वनोपज के बेहतर मूल्य हेतु वनोपज मूल्य संवर्धन विकास तथा विशिष्ट वनोपज वाले 10 क्षेत्रों को चिन्हित कर वन आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया जारी है। राज्य शासन द्वारा 32 लघुवनोपज प्रजातियों को समर्थन मूल्य घोषित किया जा चुका है।

इस वर्ष के अंत तक पांच हजार वन समितियों का माइक्रोप्लान तैयार करने का लक्ष्य है। इससे न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि ग्राम समुदाय अपनी आवश्यकता की वनोपज का उत्पादन करने के लिए आत्मनिर्भर होंगे। ग्रामों में स्थानीय समुदायों की अपेक्षाओं के अनुरूप माइक्रोप्लान बना कर प्रबंधन में लिया गया है। विगत दो वर्षों में उपचार से प्राप्त होने वाली समस्त वनोपज बांस, और जलाऊ लकड़ी वन समितियों को प्रदान की गई है, जिसका बाजार मूल्य 12 करोड़ रुपए होता है।

एक जिला एक उत्पाद - एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रदेश के 06 जिले चयनित किये गये हैं, जिसमें बैतूल जिले में सागौन, देवास, हरदा एवं रीवा में बांस तथा

अलीराजपुर एवं उमरिया जिले में महुआ उत्पाद को विकसित किया जायेगा। महुआ उत्पादन के लिए चयनित अलीराजपुर तथा उमरिया जिलों में हितग्राहियों की चयन प्रक्रिया जारी है। इन जिलों में वनोपज के उत्पादन हेतु बाह्य स्थलीय वृक्षारोपण किया जाएगा। बांस हेतु चयनित तीन जिलों के लिये पांच वर्षीय रोडमैप तैयार कर उपलब्ध बांस संसाधनों के अनुसार लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। वर्ष 2021-22 में चयनित तीन जिलों में 263 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र तथा मनरेगा योजना के अंतर्गत 360 हेक्टेयर वन क्षेत्र में बांस रोपण किया गया है। वर्ष 2022-23 हेतु तीनों जिलों में 1100 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में तथा वन क्षेत्र में मनरेगा योजना अंतर्गत 250 हेक्टेयर में एवं वन विभाग की योजनाओं में 750 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण का लक्ष्य रखा गया है। बैतूल जिले में बुडन क्लस्टर हेतु भूमि का चयन किया जा रहा है। बुडन क्लस्टर के लिये 71 निवेशकर्ताओं द्वारा लगभग 87 करोड़ रुपये निवेश कर इकाइयों की स्थापना की जायेगी। इन इकाइयों से 1600 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो सकेगा। काष्ठ विज्ञान तकनीकी संस्थान बेंगलौर में 10 छात्रों को प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है। बस्तर काष्ठ कला के शिल्पकारों द्वारा 28 प्रशिक्षार्थियों को बैतूल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

आजादी का अमृत महोत्सव - देश में आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर की स्मृति को चिरस्थाई बनाने तथा आम लोगों को इसकी भावना से अवगत कराने के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर वन विभाग द्वारा बड़ी संख्या में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। स्थानीय लोगों की भागीदारी से 536 स्थानों पर 21 हजार 158 पौधों का रोपण किया गया है।

नर्मदा नदी प्रदेश की जीवनरेखा है उसकी जलधारा को अविरल एवं निर्मल बनाए रखने के लिए जलग्रहण क्षेत्र में स्थित वन क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करने के लिए बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है। स्थानीय समुदायों के सहयोग से वर्ष 2022 में नर्मदा नदी के जलागम क्षेत्र के 18 हजार 406 हेक्टेयर क्षेत्रफल में एक करोड़ 32 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा।

जागरूकता अभियान - वन तथा वन्यजीवों के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभाग द्वारा वर्ष भर अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। हरियाली महोत्सव, वन्यप्राणी सप्ताह, अनुभूति जैसे अनेक आयोजन किये जा रहे हैं। वर्ष 2021-22 के लिए कोविड 19 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेश के शासकीय/अशासकीय विद्यालयों के लिए प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविर "अनुभूति कार्यक्रम" का आयोजन प्रदेश के सभी वन परिक्षेत्रों में सम्पन्न कराया गया है, जिसमें लगभग एक लाख 13 हजार विद्यार्थियों द्वारा शिविरों में भाग लिया गया है। इस वर्ष अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए सशुल्क अनुभूति शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

वानिकी एवं रोजगार - आजीविका एवं आमदनी के लिए स्वयं के उपयोग हेतु प्राप्त होने वाली वनोपजों के अलावा विभिन्न वानिकी गतिविधियों जैसे- वन सुधार, विदोहन, लघुवनोपज का संग्रहण एवं ईको पर्यटन से स्थानीय समुदायों हेतु प्रतिवर्ष चार करोड़ 50 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित होता है। वानिकी गतिविधियों के अलावा वन आश्रित समुदायों की युवा पीढ़ी को मुख्यधारा की आर्थिक गतिविधियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कौशल उन्नयन एवं उद्यमशीलता हेतु प्रशिक्षण कराए जाते हैं। विगत 2 वर्षों में इन गतिविधियों से लगभग पांच हजार युवाओं को नए व्यवसाय शुरू करने एवं नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं।

उद्यमशीलता एवं रोजगार के अवसरों को विस्तारित करने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा काष्ठ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्बंधित नीतियों एवं नियमों का सरलीकरण किया गया है। उद्यमियों के लिए काष्ठ चिरान अधिनियम के अंतर्गत सर्कुलर आरा (12 इंच तक) इस्तेमाल करने की छूट प्रदान की गयी है, इससे काष्ठ आधारित उद्यमों में स्वरोजगार पाने वाले लोगों को लाभ होगा।

वन विकास - प्रदेश के हरित आवरण को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जाता है। वर्ष 2021 में चार करोड़ 11 लाख पौधों का रोपण किया गया था। वर्ष 2022 में चार करोड़ 50 लाख पौधे रोपित किये जाने का

लक्ष्य है। विस्तार वानिकी परियोजना के अंतर्गत वर्षाऋतु वर्ष 2021 में गैर वन क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियों के सात लाख 34 हजार पौधों का रोपण किया गया। विभिन्न सुरक्षा बलों के माध्यम से भी तीन लाख छह हजार पौधों का रोपण किया गया है। सी.एस.आर./सी.ई.आर. के माध्यम से प्राप्त राशियों से बिगड़े वनों के सुधार हेतु नये नियम जारी किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 500 हेक्टेयर क्षेत्र में समितियों के माध्यम से वृक्षारोपण प्रस्तावित है।

वन रोपणियों में पौध तैयारी - प्रदेश में स्थापित 11 अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों की 171 रोपणियों में वर्ष 2022 के रोपण हेतु पौधा तैयारी का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2022 के रोपण हेतु रोपणियों में लगभग चार करोड़ 40 लाख पौधे एवं एक करोड़ 12 लाख सागौन रूटशूट तथा 77 लाख बांस राइजोम उपलब्ध है। वर्षाकाल 2021 में रोपणियों से चार करोड़ तीन लाख पौधों का निर्वर्तन किया गया। पौध विक्रय से सात करोड़ नौ लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

निजी क्षेत्र में वानिकी प्रोत्साहन - वनोपज की मांग और आपूर्ति के बढ़ते अंतर को कम करने के साथ ही कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि निजी भूमि पर वनीकरण को बढ़ावा दिया जाए। निजी एवं राजस्व भूमि के वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन करने के उद्देश्य से प्रदेश में "म.प्र. लोक वानिकी अधिनियम, 2001 एवं नियम 2002" के अंतर्गत प्रबंध योजना बनाई जाती है।

संयुक्त वन प्रबंधन - प्रदेश में संयुक्त वन प्रबन्धन के तहत ग्राम वन समिति, वन सुरक्षा समिति तथा ईको विकास समितियां गठित हैं। वन समितियों की कुल संख्या 15608 हैं। महिला सशक्तिकरण के तहत वन समितियों की कार्यकारिणी में 33 प्रतिशत महिलाओं की सदस्यता आरक्षित है तथा समितियों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों में से एक पद पर महिला की नियुक्ति भी अनिवार्य है।

वन संरक्षण तथा वन संवर्धन के प्रयासों में जन भागीदारी को जोड़ने के लिये ''बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण पुरस्कार योजना'' चलायी जा रही है। इसके अतिरिक्त वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए ''शहीद अमृता देवी विश्नोई'' पुरस्कार दिए जाते हैं।

अधोसंरचना निर्माण - वनों के विकास, संरक्षण एवं मानव संसाधन विकास पर पूरी क्षमता से कार्य किया जा रहा है, वहीं विभाग में अधोसंरचना के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। विभाग में फ्रंटलाइन स्टाफ हेतु आवासीय एवं कार्यालयीन भवनों का निर्माण विभाग द्वारा प्राथमिकता पर किया जा रहा है। भवनों के अतिरिक्त वन प्रबंधन हेतु वन विश्राम गृह, वाच टावर, बेरियर नाका, रपटा निर्माण, हॉस्टल आदि निर्माण कार्य कराए जाते हैं। वर्ष 2022-23 में लगभग 150 भवनों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

मानव संसाधन विकास - प्रदेश के वन बल को अनुशासित और व्यावसायिक रूप से वन प्रबंध में दक्ष करने के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। विभाग में नौ प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी - ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व सर्वविदित है, इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करने हेतु विभाग प्रयत्नशील है। विभाग के कार्यों को सुचारू बनाने के लिए कई एप्लिकेशन्स का निर्माण किया गया है। वानिकी गतिविधियों के अनुश्रवण में ''प्रबंधन सूचना प्रणाली'' के उपयोग के अतिरिक्त ''भौगोलिक सूचना प्रणाली'' का उपयोग कर एकीकृत डिजिटल मानचित्र तैयार किये गये हैं। रिमोट सेंसिंग तकनीक का वन आवरण में परिवर्तन का विश्लेषण किया जा रहा है। वन अपराधों के प्रबंधन हेतु फॉरेस्ट आफेन्स मैनेजमेंट सिस्टम तथा दावानल की रोकथाम के लिए सिम्प्लिफायर वेब का निर्माण किया गया है। मानव संसाधन प्रबंधन हेतु अधिकारी/कर्मचारी प्रबंधन प्रणाली बनाई गई है। रोपणी तथा पौधारोपण की जानकारी (स्थाई आब्जर्वेशन प्लाट के डेटा, ठेकेदार पंजीयन, डिपो पंजीयन, राष्ट्रीय परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करना, गैर वन भूमि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना अब ऑनलाइन हो गया है। विभाग में ई-आफिस का क्रियान्वयन कराया गया है।

वन संरक्षण - वन विभाग वन सुरक्षा और अवैध कटाई को रोकने के लिये प्रतिबद्ध है। वन अपराधों की गोपनीय सूचनाएं एकत्र करने के लिये मुखबिर तंत्र को प्रभावी बनाया

गया है। वन अपराधों की समय-सीमा में विवेचना के अनुश्रवण के लिये सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में 329 वन चौकियां, चार जल चौकियां, 387 बैरियर तथा 53 अंतर्राज्यीय बैरियर स्थापित हैं। वन सुरक्षा हेतु मैदानी अमले को 12 बोर की 3157 बंदूकें, 900 बायनाकुलर, 4500 मोबाइल सिम दी गई हैं। वन क्षेत्रपालों को 286 रिवाल्वर उपलब्ध कराये गये हैं। विभाग में विशेष सशस्त्र बल की तीन कंपनियां कार्यरत हैं। वन अपराधों की रोकथाम हेतु वृत्त मुख्यालय पर उड़नदस्ता कार्यरत है। वन सुरक्षा में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की सहायता भी ली जाती है। वन भूमि पर अतिक्रमण के प्रकरणों की बेदखली हेतु नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाता है।

निस्तार व्यवस्था - प्रदेश में निस्तार व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीणों को बांस, बल्ली तथा जलाऊ चट्टे प्रदाय किये जाते हैं। वर्ष 2021 में निस्तार के तहत 19 लाख 62 हजार नग बांस, 8 हजार 600 नग बल्ली तथा 43 हजार 789 जलाऊ चट्टे ग्रामीणों को उपलब्ध कराये गए हैं। निस्तार व्यवस्था के तहत ग्रामीणों/बसोड़ों को 9 करोड़ 02 लाख रुपये की रियायत दी गई।

वन उत्पादन - वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से राजस्व अर्जन में उपलब्धि बहुत अच्छी रही है। वानिकी वर्ष 2021-22 में 1.07 लाख घनमीटर इमारती काष्ठ, 52 हजार 870 नग जलाऊ चट्टे तथा 15 हजार 804 नेशनल टन बांस का उत्पादन हुआ है तथा वर्ष 2021-22 में 1444.12 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है।

वन्यप्राणी प्रबंधन - प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान तथा 24 अभ्यारण्य स्थित हैं। प्रदेश में नये क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वन्यप्राणी संरक्षण क्षेत्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ-साथ वन्यजीव पर्यटन द्वारा ग्रामीणों को उनकी आजीविका के साधन भी उपलब्ध हो रहे हैं। मध्यप्रदेश के वन्यप्राणी संरक्षण क्षेत्र में भ्रमण के लिए बेहतर सुविधाएं एवं अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। प्रदेश में वन्यप्राणी प्रबंधन के कई पहलुओं पर किये जा रहे कार्यों में तेजी लाने का प्रयास किया गया है। विशिष्ट वन्यप्राणियों को वन क्षेत्रों में स्थापित करके पर्यटन को विकसित करने के लिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका से चीता लाकर स्थापना की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। अधिकारियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अफ्रीका भेजा गया है।

मध्यप्रदेश में देश के सर्वाधिक 526 बाघ हैं, जिससे प्रदेश को बाघ राज्य का गौरव प्राप्त है। मध्यप्रदेश को ''बाघ प्रदेश'' की पहचान मिलने के बाद देश के 26 प्रतिशत तेंदुओं की संख्या 3421 के साथ मध्यप्रदेश तेंदुआ प्रदेश भी बना है, इसके अलावा 2000 घड़ियाल, 9446 गिद्ध तथा 772 भेड़िए पाये जाने का गौरव भी मध्यप्रदेश को प्राप्त है।

वन्यप्राणियों द्वारा पहुंचाई जा रही जनहानि एवं पशुहानि हेतु विभाग त्वरित क्षतिपूर्ति उपलब्ध करा रहा है। इसके साथ ही वन्यप्राणियों के स्वास्थ्य की बेहतर देखरेख करने का प्रयास भी कर रहा है। वन्यप्राणी संरक्षण तथा मानव-वन्यप्राणी द्वंद को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों के चिन्हित ग्रामों का पुनर्स्थापना किया जाना प्रावधानित है। पुनर्स्थापना का कार्य ग्रामवासियों की सहमति के उपरांत ही किया जाता है। विस्थापन के लिए प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

एस.टी.एस.एफ. द्वारा पंजीकृत वन्यप्राणी अपराध प्रकरणों की सुनवाई के लिए जबलपुर, इंदौर, होशंगाबाद, सागर तथा सतना में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। प्रदेश की वन्यप्राणी एस.टी.एस.एफ. को अंतर्राष्ट्रीय वन्यप्राणी तस्कर को पकड़ने में उल्लेखनीय सफलता पर इंटरपोल से सराहना प्राप्त हुई।

वन भूमि व्यपवर्तन - वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वर्ष 2022 में 25 प्रकरणों में भारत सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनमें सिंचाई विभाग से संबंधित 07 प्रकरणों में 224.559 हेक्टेयर वनभूमि, विद्युत परियोजनाओं के 03 प्रकरणों में 18.251 हेक्टेयर वनभूमि, रेलवे के 01 प्रकरणों में 18.65 हेक्टेयर वनभूमि, खनन 01 प्रकरणों में 12.00 हेक्टेयर तथा अन्य 13 प्रकरणों में 582.232 हेक्टेयर वनभूमि इस प्रकार कुल 855.692 हेक्टेयर वनभूमि स्वीकृत हुई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में 03 प्रकरणों में 445.45 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन की सैद्धान्तिक सहमति भी भारत सरकार से प्राप्त हुई है।

कैम्पा योजना - वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिये वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरण स्वीकृत किये जाते हैं। इन वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में स्वीकृति जारी करते समय भारत सरकार द्वारा विभिन्न शर्तें अधिरोपित की जाती हैं। इन शर्तों के अनुरूप आवेदक संस्थान से क्षतिपूर्ति रोपण, वन्यप्राणी प्रबंधन तथा एन.पी.व्ही. आदि की राशि जमा कराई जाती है। इन शर्तों का मुख्य उद्देश्य वन भूमि के व्यपवर्तन से होने वाली क्षति की पूर्ति करना है। वर्ष 2021-22 में क्षतिपूर्ति वनीकरण अंतर्गत रकबा 2765.52 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य कराया गया तथा एन.पी.व्ही. अंतर्गत रकबा 32691 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य के साथ-साथ विगत वर्षों के वानिकी कार्यों के रखरखाव एवं अन्य अधोसंरचना विकास के कार्य किये जा रहे हैं।

ग्रीन इंडिया मिशन - ग्रीन इंडिया मिशन अंतर्गत अभी तक 24577 हेक्टेयर क्षेत्र को उपचारित कर 45 लाख 84 हजार पौधों का रोपण किया गया है। वनों पर जलाऊ लकड़ी का दबाव कम करने हेतु 4618 ऊर्जा के अतिरिक्त साधनों जैसे प्रेसर कूकर, सोलर कूकर आदि का वितरण किया गया है। ईकोसिस्टम सर्विसेस इम्प्रूवमेंट परियोजना अंतर्गत मार्च 2022 की स्थिति में कुल 945463 पौधे रोपित किये गये। परियोजना अंतर्गत गतिविधियों से 30 वन समितियों के 25616 ग्रामीणों को लाभ प्राप्त हो रहा है। राष्ट्रीय वनीकरण योजना के तहत पूर्व वर्षों में तैयार किये गये वृक्षारोपणों का संधारण किया जाता है। नगर वन योजना के तहत प्रदेश के 11 नगर वन के लिए योजना स्वीकृत की गई है।

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 - वन विभाग की पांच योजनाओं को लोक सेवाओं के अंतर्गत लिया गया है। इनके तहत वन्यप्राणियों से जनहानि हेतु राहत राशि का भुगतान, वन्यप्राणियों से जनघायल हेतु राहत राशि का भुगतान, वन्यप्राणियों से पशु हानि हेतु राहत राशि का भुगतान, मालिक मकबूजा प्रकरण (पृथक लाट) में भुगतान तथा मालिक मकबूजा प्रकरण (डिपो के काष्ठ के साथ) में भुगतान सम्मिलित है।

लघु वनोपज संघ - सहकारिता की त्रिस्तरीय संरचना के माध्यम से लघु वनोपजों के संग्रहण तथा व्यापार हेतु राज्य लघु वनोपज संघ कार्य कर रहा है। प्रदेश में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के व्यापार से होने वाली समस्त शुद्ध आय का 75 प्रतिशत भाग संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरित किया जाता है। शुद्ध आय का 10 प्रतिशत वन विभाग की देख-रेख में वन विकास तथा प्रशिक्षण इत्यादि में तथा 10 प्रतिशत ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु व्यय की जाती है ।

तेन्दूपत्ता सीजन 2022 में तेन्दूपत्ता का संग्रहण प्रगति पर है तथा अभी तक 17.94 लाख मानक बोरा का संग्रहण किया जा चुका है तथा संग्राहकों को लगभग 540 करोड़ रुपये का भुगतान पारिश्रमिक के रूप में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत जनजाति बाहुल्य जिलों में लघु वनोपजों पर केन्द्रित जनजातीय समुदायों के स्वामित्व वाले बहुउद्देशीय वन धन विकास केन्द्र क्लस्टर स्थापित किये जा रहे हैं। यह केन्द्र स्थानीय रूप से उपलब्ध लघुवनोपज की खरीदी एवं मूल्य संवर्धन के लिए कार्य करेंगे। वर्तमान में प्रदेश के 14 जिलों में योजना का सफल संचालन किया जा रहा है।

संघ द्वारा संग्राहक समुदायों में संचार, पेयजल एवं सामाजिक अधोसंरचना विकसित करने के अलावा एकलव्य शिक्षा योजना के तहत 1649 विद्यार्थियों को 1.89 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई है।

वन विकास निगम - प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य निम्न कोटी के वन क्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहुमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटी के वनों में परिवर्तित करना है। सागौन तथा बांस का व्यावयायिक रोपण निगम की मुख्य गतिविधियां हैं। स्थापना के बाद से लगातार अभी तक निगम को अपने उद्देश्यों में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। निगम द्वारा वृक्षारोपणों के बेहतर प्रबंधन तथा उच्च उत्पादकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया गया है। वर्ष 2021 में वन विकास निगम द्वारा कुल 4490.352 हेक्टेयर नेट क्षेत्र में 1,07,86,124 पौधे लगाये गये हैं। वर्ष 2021-22 में निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) अंतर्गत राशि रुपये 89.88 लाख के कार्य संपादित किये गये हैं।

ईको पर्यटन विकास बोर्ड - मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड का उद्देश्य ईको पर्यटन के माध्यम से वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। बोर्ड के माध्यम से ईको पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं ताकि वनों के संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि हो सके। ईको पर्यटन गंतव्य स्थलों के विकास हेतु 141 क्षेत्र स्थल अधिसूचित किये गये हैं।

मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन - प्रदेश में बांस वनों का विकास जन आंदोलन के रूप में करने की कार्यवाही की जा रही है। बांस वनों के प्रबंधन में वन समितियों के सदस्यों को और अधिक जोड़ा जाकर बांस आधारित रोजगार का भी विस्तार किया जा रहा है। बांस आधारित विकास एवं उद्यमिता को संस्थागत रूप प्रदान करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों में बांस शिल्पकारों एवं बांस उद्यमियों का विकास तथा बांस उत्पादों का प्रभावी विपणन सम्मिलित है।

निजी क्षेत्र की 8 बांस इकाइयों एवं 2 बांस रोपणियों को स्वीकृत किया गया है, जिसमें हितग्राहियों को 101.08 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। प्रदेश के 6 जिलों (धार, बड़वानी, सतना, खण्डवा, सीधी एवं अलीराजपुर) में एफ.पी.ओ. (Farmer Producer Organization) का निर्माण नाफेड के सहयोग से प्रारंभ करवाया गया है।

वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजना के अंतर्गत वनक्षेत्रों ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के उद्देश्यों से स्व-सहायता समूह के माध्यम से लगभग 5200 हे. क्षेत्र में बांस रोपण प्रस्तावित है। इस हेतु आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, साथ ही गैर वन क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में लगभग 3750 हे. भूमि पर बांस रोपण का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार से वन क्षेत्रों के बाहर वन उत्पादन बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूण कदम उठाया गया है।

जैवविविधता बोर्ड - प्रदेश में जैवविविधता को संरक्षण, उसके संघटकों का संवहनीय (पोषणीय) उपयोग तथा जैव संसाधनों और ज्ञान के वाणिज्यिक (व्यापारात्मक) उपयोग से उद्भूत लाभ का उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन के लिए बोर्ड प्रतिबद्ध है। प्रदेश के विद्यार्थियों में जैवविविधता जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय मध्यप्रदेश जैवविविधता क्विज़ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैवविविधता प्रबंधन समितियों का उन्मुखीकरण एवं लोक जैवविविधता पंजी अद्यतनीकरण हेतु कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर जारी है।

रमेश कुमार गुप्ता
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं
वन बल प्रमुख, म.प्र.

अपना सच्चा धर्म निभाएं,
पेड़ बचाकर कर्तव्य निभाएं।

वन समितियों के लाभांश में वृद्धि : वन समिति सम्मेलन, भोपाल

वनोपज के संग्रहण व्यापार से वनवासियों को लाभ दिलाने की दृष्टि से वर्ष 1984 में मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत हुआ। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1988 में लघुवनोपज के संग्रहण, भण्डारण एवं व्यापार से बिचौलियों को पूर्णत: समाप्त करने के लिये वास्तविक संग्रहणकर्ताओं की त्रिस्तरीय सहकारी संस्थाओं का गठन किया गया। प्राथमिक स्तर पर वास्तविक संग्राहकों की सदस्यता से 1072 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां, जिला स्तर पर 60 जिला वनोपज सहकारी यूनियन तथा शीर्ष स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, कार्यरत है। वर्तमान में मात्र तेंदूपत्ता के विपणन को छोड़कर शेष अन्य लघुवनोपज जैसे हर्रा, बहेड़ा, लाख, अचार, महुआ, शहद, माहुल पत्ता, आंवला एवं औषधीय वनोपजों का संग्रहण एवं विपणन करने की ग्रामीणों को स्वतंत्रता है। मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज संघ ने संग्राहकों को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से 32 लघुवनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है ताकि उन्हें बेहतर आर्थिक लाभ मिल सके।

तेंदूपत्ता संग्रहण एवं निर्वर्तन की जानकारी

संग्रहण वर्ष	संग्रहण दर (रु. प्रति मा.बो.)	कुल संग्रहित मात्रा (लाख मा.बो.में)	संग्रहण मजदूरी की राशि (करोड़ रुपये में)	विक्रीत मात्रा	विक्रय मूल्य (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6
2019	2500	21.04	525.00	20.38	841.68
2020	2500	15.88	397.00	14.72	589.49
2021	2500	16.60	415.00	16.32	842.30

शुद्ध आय का वितरण - संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप लघुवनोपज का स्वामित्व ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। प्रदेश में लघुवनोपज व्यवसाय से ग्रामीणों को उचित लाभ दिलाने के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिये गये हैं। लघु वनोपज के अंतर्गत तेंदूपत्ता के व्यवसाय से होने वाली संपूर्ण शुद्ध आय प्राथमिक सहकारी वनोपज समितियों को उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में शुद्ध आय का 75

प्रतिशत भाग संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित मात्रा के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में भुगतान करने का प्रावधान है। शेष 25 प्रतिशत में से 10 प्रतिशत भाग वनों के संवर्धन पर लगाया जा रहा है तथा 10 प्रतिशत की अवशेष राशि प्राथमिक लघुवनोपज सहकारी समितियों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनकी माँग अनुसार ग्राम की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु दी जा रही है। हाल ही में शासन द्वारा शुद्ध आय का 5 प्रतिशत आय ग्राम सभाओं को निर्माणाधीन सामुदायिक वन समितियों को भी आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।

तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक की जानकारी

संग्रहण वर्ष	प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि (रुपये करोड़ में)	
	कुल आंकलित	कुल वितरित राशि
2017	538.48	557.31
2018	266.11	242.32
2019	125.24	119.54
2020	70.16	66.80
योग	**1044.99**	**985.97**

लघु वनोपज समितियों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत तेंदूपत्ता बोनस वितरण सम्मेलन का आयोजन श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार के मुख्य आतिथ्य एवं श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 22.04.2022 को भोपाल के जम्बूरी मैदान में किया गया।

कार्यक्रम में केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय जनशक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय मतस्य-पालन, पशुपालन, डेयरी और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री श्री एल. मुरुगन, सांसद श्री वी.डी. शर्मा, वरिष्ठ नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय, श्री ओम प्रकाश धुर्वे, सांसद सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर, श्री कल सिंह भाबर, मध्यप्रदेश के वन मंत्री श्री विजय शाह, गृह, जेल और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी को जनजातीय संस्कृति के प्रतीकस्वरूप पारंपरिक तीर-कमान और जैकेट भेंट किए गए।

कार्यक्रम के आरंभ में वन मंत्री डॉ. कुँवर विजय शाह ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश में वनों को बचाते हुए समग्र विकास की दिशा में कार्य हो रहा है। जंगल न कटें, वनवासी इसे अपना समझें, उन्हें 20 प्रतिशत लाभांश देने वाली यह पहली सरकार है। प्रदेश में करीब एक हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष सरकार को वनों से आय मिलती थी। अब उसका हिस्सा वनवासियों को मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह जल, जमीन और जंगल वनवासियों के हैं। वनों से अर्जित आय का हिस्सा प्राप्त कर वनवासी, वनों के विकास में सहयोग करेंगे। वन विभाग सहयोगी की भूमिका में रहकर वनों का प्रबंधन करेगा। कार्यक्रम में तेंदूपत्ता संग्राहकों को 250 रुपये प्रति सौ गड्डी के स्थान पर अब 300 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अपने उद्बोधन में कहा कि मध्यप्रदेश, वनवासियों को वन क्षेत्र का मालिक बनाने वाला देश का पहला राज्य है। मध्यप्रदेश ने यह युग परिवर्तनकारी कार्य किया है। मध्यप्रदेश में देश की सबसे अधिक 21 प्रतिशत जनजाति आबादी निवास करती है। इनके कल्याण के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने सराहनीय कार्य किया है।

हितग्राहियों को दिये गये हित-लाभ केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 5 तेंदूपत्ता संग्राहकों श्रीमती ललिता बाई सीहोर, श्रीमती संतोष रायसेन, श्री अमर सिंह नर्मदापुरम, श्री सजन सिंह देवास और श्रीमती लक्ष्मीबाई हरदा को वर्ष 2020 का प्रतीकस्वरूप प्रोत्साहन पारिश्रमिक प्रदान किया। बोनस की शेष राशि का वितरण जिला यूनियनवार पृथक से किए जाने की योजना बनाई गई है।

कार्यक्रम के अंत में श्री पुष्कर सिंह, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज संघ द्वारा वन समितियों एवं लघुवनोपज समितियों की क्षमता वृद्धि हेतु आयोजित प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, कार्यक्रम के अध्यक्ष, मंचासीन अतिथियों एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों, अधिकारीगण, प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उपस्थित जनसमुदाय एवं व्यवस्था प्रबंधन मे लगे अधिकारी कर्मचारियों का हृदय से आभार व्यक्त किया गया।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कार्यक्रम स्थल पर वन विभाग द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रदर्शनी में विंध्य हर्बल्स द्वारा बनाए जा रहे आयुर्वेदिक उत्पादों, नरसिंहपुर जिले के सतपुड़ा रस्सी निर्माण केंद्र द्वारा रस्सी निर्माण एवं रेहटी प्रसंस्करण केन्द्र के उत्पादों, मंडला, डिंडौरी, छिंदवाड़ा एवं सिवनी के वन धन विकास केन्द्रों द्वारा तैयार उत्पादों के कार्यों का प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने समिति के सदस्यों से रस्सी निर्माण एवं विंध्य हर्बल्स उत्पादों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विभिन्न उत्पादों का अवलोकन कर प्रदर्शनी की सराहना की।

वन एवं वन्यजीव संरक्षण जागरूकता अभियान : वन विहार राष्ट्रीय उद्यान

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान-जू, मध्यप्रदेश की राजधानी के हृदय स्थल में स्थित नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगह है। इसका कुल क्षेत्रफल 445.21 हेक्टेयर है। प्रतिवर्ष लगभग छ: लाख पर्यटक यहाँ भ्रमण हेतु आते हैं। वन विहार में लगातार वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण से संबंधित शैक्षणिक तथा विकास संबंधी गतिविधियाँ प्रचलित रहती हैं। इस त्रैमास जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 के मध्य अनेकों कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है-

अनुभूति कैंप - मध्यप्रदेश शासन वन विभाग द्वारा अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत वन, वन्यप्राणी एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड के समन्वय से आयोजित प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविर के अंतर्गत वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में अनुभूति शिविर क्रमश: दिनांक 04.01.2022, 06.01.2022, 12.01.2022, 13.01.2022, 07.03.2022 एवं 09.03.2022 को कुल छह कैंप आयोजित किये गये जिसमें कुल 732 विद्यार्थियों, शिक्षकों द्वारा भाग लिया गया। इन शिविरों के दौरान शिविर में सम्मिलित हुये प्रत्येक बच्चे को अनुभूति बैग, कैप, पठनीय सामग्री, मुन्ना की कहानी, स्टीकर/पोस्टर, की - रिंग, बैच प्रदान किये गये। साथ ही विद्यार्थियों को पक्षी दर्शन, वन्यप्राणी दर्शन, प्रकृति पथ भ्रमण एवं वन्यप्राणियों के कटआउट्स के माध्यम से स्थल पर विद्यमान वानिकी गतिविधियों की जानकारी, वन, वन्यप्राणी व पर्यावरण से संबंधित रोचक गतिविधियाँ कराई गईं तथा जानकारी प्रदान कर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया गया। विद्यार्थियों को वन्यप्राणियों को कैसे रेस्क्यू किया जाता है, इसके सम्बंध में रेस्क्यू वाहन के माध्यम से रेस्क्यू टीम द्वारा अवगत कराया गया। कार्यक्रम के अंत में शिविर में सम्मिलित बच्चों को शपथ दिलाई जाकर पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र वितरण किये गये।

नेचर ट्रेल - राज्य स्तरीय वन्यप्राणी वर्ष 2021 के समापन कार्यक्रम अवसर पर वन विहार प्रबंधन द्वारा यह संकल्प लिया गया था कि वन विहार में जिज्ञासु पर्यटकों हेतु एक नेचर ट्रेल का निर्माण किया जायेगा, जिसमें वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण से संबंधित अधिकतर घटकों का समावेश होगा। दिनांक 15.01.2022 से प्रति शनिवार को प्रकृति पथ भ्रमण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसमें 20 महत्वपूर्ण स्थल हैं।

इसकी पथ की कुल लंबाई 2.4 किमी. है जिसका प्रारंभ रामसर साइट बड़ा तालाब से प्रारंभ होकर बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर, तितली पार्क, स्नेक पार्क के सामने से होता हुआ वन विहार के अंदरूनी क्षेत्रों से गुजरता है जिसमें दीमक की बामी, वन्यप्राणियों के सींग-श्रृंगाभ, लेंडियाँ (Droppings) पंख, बैलोइंग पांड्स, सेही गुफा, वन का प्रकार, घास का मैदान, बारासिंगा बाड़ा, पी.एम. हाउस, बैंबू सीटम, कदम्ब का वृक्ष आदि से होता हुआ घड़ियाल मगर बाड़ा - पक्षी विहार से वापस वन विहार वीथिका पर समाप्त होता है। ये कैंप सशुल्क आयोजित होते हैं जिसमें प्रथम रामू पैकेज रुपये 250/- एवं द्वितीय चीकू पैकेज रुपये 500/- का है। प्रकृति पथ भ्रमण दौरान विशेषज्ञ रिसोर्स पर्सन साथ में रहकर महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं।

बैट्री ऑपरेटेड वाहन एवं टॉय ट्रेन का शुभारंभ - वन विहार प्रबंधन मध्यप्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप बेहतर पर्यावरण हेतु प्रयत्नशील रहा है। नवीन वर्ष के प्रारंभ में वन विहार में बैट्री ऑपरेटेड वाहन का शुभारंभ 18.01.2022 एवं टॉय ट्रेन का शुभारंभ पी.पी.पी. मोड पर प्रारंभ किया गया। इससे न केवल पर्यावरण समृद्ध होगा बल्कि पर्यटकों को भी वन विहार के भ्रमण में अत्यंत आनंद की अनुभूति होगी।

विंटर बर्ड काउंट - भोज वेटलैंड भोपाल में दिनांक 19.12.2021 से पक्षियों की गणना के कार्य का प्रथम चरण भोपाल बर्ड्स, मध्यप्रदेश राज्य वेटलैंड अथॉरिटी, एप्को, वी.एन.एस. नेचर सेवियर्स एवं वन विहार के संयुक्त तत्वावधान में प्रारंभ किया जाकर तीन चरणों में दिनांक 02.02.2022 को समाप्त किया गया। इस गणना में लगभग 30 पक्षी प्रेमी एवं विशेषज्ञों द्वारा भाग लिया गया। इस गणना में पक्षियों की 210 प्रजाति पाई गईं। विगत दशक में 266 प्रजाति चिन्हित की जा चुकी हैं जो कि वन विहार के स्वस्थ पर्यावरण का प्रतीक है। इस गणनाकाल के दौरान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के भीतर पहली बार यूरेशियन ग्रिफन गिद्ध प्रजाति के चार पक्षी देखे गये। इसके अलावा इग्रेट, हेरोन, कारमोरेंट, स्पॉट बिल्ड डक, ब्लैक काइट, किंग फिशर, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, सनबर्ड, जकाना, कॉमन पोचार्ड, श्राइक, रेड वेटल्ड लेप विंग, रिवर टर्न आदि बड़ी संख्या में पक्षी पाये गये।

वन्यप्राणी अंगीकरण योजना - वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वन्यप्राणी अंगीकरण योजना 01 जनवरी 2009 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय ने एक बार पुन: पर्यावरण तथा वन्यप्राणियों के संरक्षण के प्रति प्रेम की ओर अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुये एक साथ एक नर बाघ पन्ना तथा मादा बाघ रिद्धी को दिनांक 23.02.2022 से एक वर्ष के लिये गोद लिया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 31.01.2010 को प्रथम बार मादा बाघ सीता को एक वर्ष के लिये गोद लिया गया था। उसके पश्चात आज दिनांक 23.02.2022 तक 15 वन्यप्राणियों को गोद लिया जा चुका है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वन्यप्राणियों को लगातार गोद लेने के साथ-साथ वन विहार को इस वर्ष उनके द्वारा 30 साइकिलें एवं 25 डस्टबिन प्रदाय किये गये हैं।

नाइट सफारी का पुन: प्रारंभ - माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश

शासन के निर्देश पर वन विहार में रात्रिकालीन सफारी का शुभारंभ माननीय मंत्री वन मध्यप्रदेश शासन द्वारा 04 मार्च 2021 से किया गया था जिसे विगत वर्ष में ही कोरोना संक्रमण काल के दौरान बंद कर दिया गया था। इस नाइट सफारी का पुन: प्रारंभ इस वर्ष 07 मार्च 2022 से किया गया है जिसमें पर्यटकों द्वारा पूरे उत्साह के साथ भ्रमण किया जा रहा है।

महिला दिवस नेचर कैंप - दिनांक 08.03.2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नेचर कैंप/बर्ड वाचिंग कैंप का आयोजित किया गया जिसमें भारतीय स्टेट बैंक समूह तथा शासकीय महिला पॉलिटेक्निक की 130 महिलाओं द्वारा भाग लिया गया।

चीतल ट्रांसलोकेशन - वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल के स्थापनाकाल के बाद से लगातार वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता से वन विहार में शाकाहारी वन्यप्राणियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक मध्यप्रदेश के आदेशानुसार वन विहार से चीतलों का ट्रांसलोकेशन गांधीसागर अभ्यारण्य एवं खिवनी अभ्यारण्य वनमंडल देवास को किया जा रहा है। अभी तक गांधी सागर अभ्यारण्य को 22 चीतल तथा खिवनी अभ्यारण्य देवास वनमंडल को 45 चीतल स्थानांतरित किये जा चुके हैं।

सरलीकृत हुई संग्रहित लघु वनोपज की निर्वर्तन प्रक्रिया

वनोपज अंतर्विभागीय समिति की हुई बैठक में वन मंत्री डॉ. कुँवर विजय शाह ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्रहित लघु वनोपज के निर्वर्तन प्रक्रिया को सरलीकृत बनाया जाए। इससे राज्य लघु वनोपज की आय में वृद्धि होने के साथ इस कार्य में जुड़े गरीब तबके को फायदा मिल सकेगा। वन मंत्री डॉ. कुँवर विजय शाह ने निर्देश दिए कि संग्रहित लघु वनोपज की नीलामी प्रक्रिया में जिला स्तर पर अधिकार प्रत्यायोजित किए जाएँ, जिससे लघु वनोपज की नीलामी प्रक्रिया समय-सीमा में पूरी की जा सके।

राज्य लघु वनोपज के प्रबंध संचालक श्री पुष्कर सिंह ने बताया कि केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ द्वारा प्रायोजित "न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना" में प्रदेश में लघु वनोपज का संग्रहण कार्य किया जा रहा है। अभी तक 32 लघुवनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जा चुके हैं।

लघुवनोपज के 2 नए उत्पाद परीक्षण के बाद होंगे लॉन्च-

वन मंत्री डॉ. शाह ने म.प्र. लघुवनोपज प्र-संस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र बरखेड़ा पठानी द्वारा तैयार किए जा रहे कोल्ड ड्रिंग्स, मधु कोला और जम्मू कोला के सैम्पल को बहुत अच्छा बताया। इस नए उत्पाद का परीक्षण के बाद व्यापक स्तर पर एक कार्यशाला आयोजित की जाए। वन मंत्री डॉ. कुँवर विजय शाह ने कहा कि इन दोनों उत्पाद की विश्वसनीयता का परीक्षण और अन्य प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद उत्पादों को लॉन्च किया जाए। बैठक में बताया गया कि इन दोनों उत्पाद को मार्केट में लॉन्च किए जाने से इसका विपणन शीर्ष स्तर पर पहुँचेगा। इस अवसर प्रमुख सचिव वन श्री अशोक बर्णवाल एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री आर.के. गुप्ता सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे।

डॉ. कुँवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री, वन, म.प्र. शासन द्वारा : वन विहार राष्ट्रीय उद्यान-जू में वाईल्ड केफे का पुन: शुभारंभ

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान- जू भोपाल के प्रवेश द्वार क्र. 2 के समीप पर्यटकों की सुविधा हेतु वाइल्ड केफे स्थापित है। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण उक्त केफे विगत दो वर्षों से बंद था। पर्यटकों की सुविधा हेतु दिनांक 12.04.2022 को उक्त वाइल्ड केफे का पुन: शुभारंभ डॉ. कुँवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री, वन म.प्र. शासन द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री रमेश कुमार गुप्ता, प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य वन विकास निगम, डॉ. अभय पाटिल, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, श्री जे.एस. चौहान, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अनु.वि.एवं लो.वा.), श्री असीम श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (विकास), श्री चितरंजन त्यागी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू-अभिलेख), डॉ. अतुल श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. ईको पर्यटन विकास बोर्ड, श्री सत्यानंद, मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल, श्री रवीन्द्र सक्सेना, संचालक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, श्री एच.सी. गुप्ता, सहायक संचालक वन विहार, श्री ए.के. जैन एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं मीडियाकर्मी भी उपस्थित रहे।

वाइल्ड केफे का संचालन श्री अश्विनी रिछारिया द्वारा किया जावेगा। संचालनकर्ता द्वारा पर्यटकों की सेहत का पूर्ण ध्यान रखते हुये वाइल्ड केफे में अंकुरित आहार, जिसमें 7-8 प्रकार के अंकुरित सलाद के अतिरिक्त फ्रूट सलाद, फ्रेस जूस, स्मूदिज, मल्टीग्रेन डोसा आदि निर्धारित दर पर प्रदाय किया जावेगा।

ई व्हीकल से वन विहार आने वाले पर्यटकों को संचालनकर्ता द्वारा वाईल्ड केफे में 15 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जावेगी। इसके साथ ही वन विहार प्रबंधन द्वारा भविष्य में पर्यटकों को कोम्बो पैकेज जिसमें सफारी के साथ-साथ लंच एवं ब्रंच की सुविधा भी दिया जाना प्रस्तावित है।

प्रथम पक्षी सर्वेक्षण : पेंच टाइगर रिजर्व

पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी का प्रथम पक्षी सर्वेक्षण दिनांक 27 से 30 जनवरी तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इंदौर की संस्था वाइल्डलाइफ एण्ड नेचर कन्जरवेंसी के सहयोग से आयोजित इस सर्वेक्षण कार्य में 10 राज्यों के 65 पक्षी विशेषज्ञों ने भाग लिया। दिनांक 27 जनवरी को सभी पक्षी विशेषज्ञ करमाझिरी में एकत्रित हुए। जहाँ पंजीयन कार्य पूर्ण कर 1 से 2 सदस्यों का दल गठित कर पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी के विभिन्न परिक्षेत्रों अंतर्गत चिन्हित स्थलों में भेजा गया। स्थानीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से पक्षी विशेषज्ञ दल द्वारा ट्रांसेक्ट लाइन और ट्रेल पर चलकर पक्षी सर्वेक्षण का कार्य दिनांक 28 और 29 जनवरी को सुबह और शाम की दो-दो पालियों में मोबाइल एप्लीकेशन ई-बर्ड के माध्यम से किया गया। पक्षी सर्वेक्षण के उपरांत दिनांक 30 जनवरी को सभी दल पुन: करमाझिरी में एकत्रित हुए जहाँ सर्वेक्षण के उपरांत प्राप्त डेटा का संकलन कार्य किया गया। इस प्राप्त डेटा का गहनता विश्लेषण उपरांत एक विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होगी जिससे पेंच टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में पक्षियों की प्रजातियों की वास्तविक जानकारी प्राप्त होगी।

वाइल्डलाइफ एन्ड नेचर कन्जरवेंसी संस्था के प्रमुख श्री राजेन्द्र बागड़ा जी ने जानकारी दी है कि इस अंतिम रिपोर्ट तैयार होने में लगभग 3 माह का समय लग सकता है

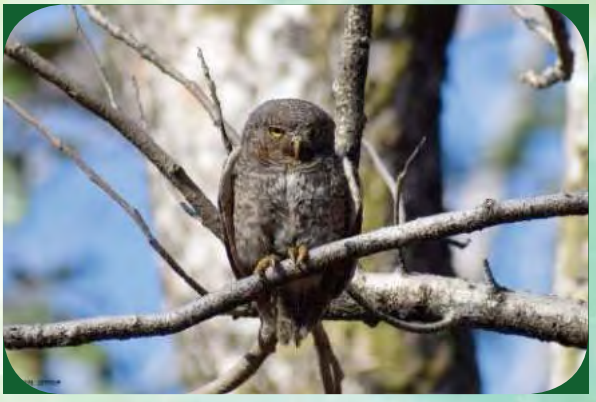

साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी सर्वेक्षण के दौरान स्थानीय प्रजातियों के साथ-साथ प्रवासी पक्षियों की भी बहुत सी प्रजातियां दिखाई दी हैं एवं कुछ अत्यंत कम दिखने

रिजर्व सिवनी के क्षेत्र संचालक श्री अशोक मिश्रा ने वाइल्डलाइफ एण्ड नेचर कन्जरवेंसी संस्था एवं सर्वेक्षण हेतु पधारे समस्त पक्षी सर्वेक्षकों को उनके प्रयास हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया और विश्वास दिलाया कि इस सर्वेक्षण के उपरांत प्राप्त रिपोर्ट निश्चित ही पक्षी प्रबंधन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी इससे प्रबंधन हेतु नए कार्य करने के अवसर मिलेंगे और पेंच टाइगर रिजर्व जो कि वर्तमान में अपने टाइगर्स के लिए जाना जाता है वो निकट भविष्य में पक्षियों के लिए भी पहचाना जावेगा। इस सम्पूर्ण पक्षी सर्वेक्षण कार्य मे पेंच टाइगर रिजर्व के उप संचालक श्री अधर गुप्ता, सहायक वन संरक्षक सिवनी क्षेत्र श्री बी.पी. तिवारी, सहायक वन संरक्षक छिंदवाड़ा क्षेत्र श्रीमती भारती ठाकरे, अधीक्षक पेंच मोगली अभ्यारण्य श्री आशीष पांडेय, वन्य प्राणी चिकित्सक श्री अखिलेश मिश्रा एवम् समस्त परिक्षेत्र अधिकारियों सहित समस्त स्थानीय स्टाफ का भी महत्वपूर्ण सक्रिय योगदान रहा।

वाली प्रजातियां जैसे टिकल्स थ्रश, बल्यथ पिपिट, टिकल्स लीफ वार्बलर, फेरुजीनस डक, ब्लैक कैप्ड थ्रश, ग्रिफन वल्चर, ब्लैक कैप्ड किंगफिशर आदि इस सर्वेक्षण के दौरान पाई गई हैं , उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस सर्वेक्षण से 250 से अधिक प्रजातियों की उपस्थिति ज्ञात हो सकती है। इसी संस्था के सदस्य श्री राजेश मंगल ने सम्पूर्ण सर्वेक्षण कार्य मे पेंच प्रबंधन द्वारा की गई तैयारियों एवं अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका की सराहना की है। पेंच टाइगर

मन्धान जलग्रहण क्षेत्र उपचार परियोजना (Catchment Area Treatment) से क्षेत्र का समग्र विकास

KK Bhardwaj, APPCF, Chhindwara Ishwar Jarande DFO (West) Chhindwara

मन्धान बांध पेंचव्हेली के मन्धान नदी जो कि पेंच की उपनदी है, पर बनाया गया है। जिसकी पानी रोकने की क्षमता 5.3 MCM है। उक्त परियोजना के मास्टर प्लान में जलग्रहण क्षेत्र का CAMPA के माध्यम से समग्र उपचार का प्रावधान किया गया है।

मन्धान नदी का जलग्रहण क्षेत्र तीव्र पहाड़ी, उथली मृदा वाला क्षेत्र है जो भू-क्षरण के लिये अत्यंत प्रवल है, वनक्षेत्र का प्रतिशत कम है एवं जो वन क्षेत्र है वह विरल एवं जैविक दबाव के कारण बिगड़ा वनक्षेत्र है। इस प्रकार से जलग्रहण क्षेत्र में मृदा अवसादन के कारण बांध की उपयुक्त आयु कम हो जाती है, साथ ही जलग्रहण कम होने के कारण पानी सतह से बहकर पानी की वार्षिक उपलब्धता भी प्रभावित होती है। जलग्रहण उपचार परियोजना का मुख्य उद्देश्य जलग्रहण क्षेत्र में मृदा क्षरण को रोकना एवं पानी का भूमि में रिसाव बढ़ाना है।

उक्त परियोजना में कुल 29.97 हे. भूमि प्रस्तावित हुई है जिसमें से 17.725 हे. वनभूमि है। मन्धान नदी का जलग्रहण क्षेत्र 10878 हेक्टेयर है। जो 24 गांवों में विस्तारित है जिसमें से 6 गांव पूर्णत: जलग्रहण क्षेत्र में आते हैं तथा शेष 18 गांव अंतत: जलग्रहण क्षेत्र में आते हैं, समस्त गांवों में कृषि मुख्यत: प्राथमिक व्यवसाय है, प्रति किसान भूमि धारण कम है तथा मिट्टी उथली एवं मुरमी किस्म है। परियोजना में आस्थामूलक कार्य भी शामिल किये गये हैं। जिसका उद्देश्य ग्रामीणों का परियोजना में सहभागिता बढ़ाना तथा परियोजना को सफल बनाने में मदद करना है।

1. जैविक उपचार

वृक्षारोपण - जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिगड़े वनों के सुधार हेतु 35 हे. वनभूमि पर तथा 12 हे. राजस्व भूमि पर मिश्रित वृक्षारोपण किया गया है। जिसमें मुख्यत: मिश्रित प्रजाति का रोपण किया गया है। जहां उथली एवं पथरीली मृदा है उन स्थानों पर Glericidia का रोपण कर मृदा में उमस बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।

चारागाह विकास - जलग्रहण क्षेत्र के 15 हे. वनभूमि पर चारागाह एवं जलाऊ रोपण किया है। वृक्षारोपण में दीनानाथ, काँदी इत्यादि घास प्रचुर मात्रा में आई है जो भू एवं मृदा संरक्षण कार्य करेगी साथ ही स्थानीय कृषकों को दुग्ध विकास में मददगार साबित होगी।

परियोजना के अंतर्गत ही एक नर्सरी स्थापित कर 2.4 लाख फलदार पौधे तैयार किये गये हैं। जिसमें से एक लाख पौधों का किसानों की मेड़ पर रोपण किया गया है।

जैविक हेज - कंटूर पर जैविक हेज रोपण से पानी की गति

को कम करना तथा उसका रिसाव बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा यह कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

2. अभियांत्रिकी उपचार

क्षेत्र के नालों के उद्गम स्थलों पर जहां नाली बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है वहां गली प्लग निर्माण कर नाले के विस्तारण को रोका जा रहा है। कम ढलान वाले क्षेत्र में जहां पानी का बहाव तीव्र नहीं है वहां लूज बोल्डर चेकडैम बनाए गए हैं, तीव्र ढलान एवं जहां पानी का बहाव तीव्र है, उन स्थानों पर गेबीयन स्ट्रक्चर बनाए गए जो अत्यंत कारगर साबित हो रहे हैं।

कृषकों के खेतों में मृदा के sheet erosion को रोकने के लिए continuous कंटूर बंड इत्यादि के माध्यम से मृदा एवं जल संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। Continuous contour bund के माध्यम से बनाए गए मेढ़ों से मृदा का क्षरण कम हुआ है तथा खेती के लिए बंजर जमीन उपलब्ध हो रही है।

(3) आस्थामूलक कार्य

मन्धान जलग्रहण क्षेत्र में 24 ग्राम आते हैं। उक्त गांवों में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु केंचुआ खाद निर्माण करना, गौमूत्र एकत्रित कर उससे ग्रोथ हॉरमोन तथा कीटनाशक बनाना इत्यादि कार्यों के लिए सामग्री वितरित की गयी है। केंचुआ खाद बनाने के लिए HDPE टेट्रा वर्मी बेड और उनके साथ केंचुए प्रदाय किए गए हैं। कृषकों के द्वारा उक्त बैड में केंचुआ खाद निर्माण किया जा रहा है। एक आवर्तन में प्रति बैड 500 कि.ग्रा. केंचुआ खाद बनाया जा रहा है, जो लगभग 45 दिनों में बनकर तैयार हो जाता है। ग्राम काजरा के 100 कृषकों द्वारा अभी तक 5 आवर्तन में कुल 2500 क्विटंल केंचुआ खाद तैयार की गई है।

कृषकों के द्वारा केंचुआ खाद तैयार कर मक्का, धान आदि फसलों में उपयोग किया है। उक्त फसलों के उत्पादन में केंचुआ खाद के उपयोग से आ रहे सकारात्मक बदलाव का अनुश्रवण भी किया जा रहा है।

प्राथमिक रूप से मक्का एवं धान के परिणामों के अनुश्रवण से इन फसलों की ऊँचाई में बढ़त दिखी है साथ ही भुट्टों के आकार में भी बढ़त पाई गयी है। केंचुआ खाद के उपयोग से कृषि उत्पाद में तो बढ़ोतरी हुई है साथ ही रासायनिक खाद की लागत शून्य हुई है जिससे निवल आय में लक्षणीय बढ़ोतरी हुई है।

कृषकों के द्वारा मांग के अनुसार गौशालाओं को कांक्रीट से लोरिंग कर गोमूत्र एकत्रित कर टॉनिक एवं कीटनाशक तैयार किया जा रहा है। इस प्रकार जलग्रहण क्षेत्र में जैविक खेती से ना केवल उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी बल्कि बांध के पानी में जाने वाले रासायनिक अवशेष में भी कमी आयेगी जिससे पानी की शुद्धता बनी रहेगी तथा जैव विविधता का संरक्षण भी होगा।

परिणामों का अनुश्रवण

परिणामों के अनुश्रवण हेतु समस्त गेबीयन स्ट्रक्चर, बोल्डर चेकडैम इत्यादि के ऊपरी सतह पर सीमेन्ट के पोल गाड़ कर इन संरचनाओं के द्वारा रोकी गई सिल्ट का वर्षा के मौसम में हर महीने के बाद अनुश्रवण किया जा रहा है।

जल संवर्धन कार्यों के परिणामों के अनुश्रवण हेतु जलग्रहण क्षेत्र में मौजूद कुओं के पानी का हर माह जलस्तर नाप कर उसके जलस्तर में आ रहे बदलाव का अनुश्रवण किया जा रहा है।

वृक्षारोपण क्षेत्र का मूल्यांकन भी वर्ष में दो बार किया जा रहा है।

जलग्रहण क्षेत्र के उपचार के कारण बंजर भूमि से कृषि योग्य भूमि में होने वाले परिवर्तन, कृषि भूमि का एक से अधिक फसलों के लिए उपयोग इत्यादि का भी अनुश्रवण किया जा रहा है।

भविष्य की रणनीति

जलग्रहण क्षेत्र उपचार हेतु कुल स्वीकृत राशि के केवल 16 प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया है जिससे इतने सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। उक्त सकारात्मक परिणाम ना केवल आम जनता की उक्त परियोजना में सक्रिय सहभागिता बढ़ा रही है बल्कि वन कर्मचारी जो इस योजना में अपना योगदान दे रहे हैं उनमें भी उत्साहवर्धन कर और अच्छे परिणामों के लिये कटिबद्ध कर रहे हैं।

म.प्र. राज्य बांस मिशन द्वारा वन-कर्मियों को बांस के तकनीकी विशेषज्ञ बनाने हेतु प्रशिक्षण

बांस खेती के इच्छुक कृषकों एवं उद्यमियों को मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन की योजनाओं की जानकारी प्रदान करने का नेटवर्क विकसित करने हेतु भोपाल में 74 बंगले, खेल परिसर स्थित कमांड रूम में दिनांक 17.06.2022 को वन-कर्मियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया ।

इस प्रशिक्षण में वन विभाग के 53 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य इन कर्मचारियों को बांस के तकनीकी विशेषज्ञों के रूप में विकसित करना है।प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव, वन विभाग ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर जोर दिया :-

- प्रदेश में बांस कृषि को एक लाभकारी बिज़नेस मॉडल के रूप में प्रोत्साहित किया जावे जिससे अधिक से अधिक किसान इसे अपनाने हेतु प्रेरित होंगे एवं लम्बी अवधि में उनकी सरकार पर निर्भरता कम होगी।
- मध्यप्रदेश को “Bamboo Capital” बनाने हेतु पूरे मानयोग से प्रयास किया जावें। आगामी 10 वर्षों में कृषि भूमि में बांस रोपण का लक्ष्य 1 लाख हेक्टेयर रखा गया है जिससे प्रति वर्ष 60 लाख टन बांस की खपत हो सकेगी। जब प्रदेश में बांस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा तो बड़े उद्योग यहाँ अपनी इकाई स्थापित करने के लिए आकर्षित होंगे।
- राज्य में स्थित बांस की खपत करने वाले बड़े उद्योग जैसे ओरिएंट पेपर मिल्स द्वारा कृषकों के साथ बाय-बेक अग्रीमेंट्स तैयार किया गए हैं। इस पेपर मिल से आस-पास के अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने हेतु विभाग द्वारा प्रयास किये जावें। इस प्रकार के अग्रीमेंट्स होने से कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा एवं वे बांस की खेती करने हेतु प्रोत्साहित होंगे। इसके साथ ही उद्योंगों को उनकी खपत हेतु कच्चे माल के नियमित सप्लाई का स्रोत मिलेगा। इस तरह के प्रयासों से डिमांड-सप्लाई के गैप को पूरा किया जा सकेगा एवं राज्य में बांस क्षेत्र का सतत विकास होगा।
- बांस की व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियाँ जैसे:- कटंग, बाल्कूआ, टुल्डा, आदि को प्रदेश में रोपण हेतु बढ़ावा दिया जावे। इन प्रजातियों की बांस फर्नीचर, निर्माण, अगरबत्ती इकाइयाँ, आदि प्रमुख उद्योगों में मांग होने से कृषकों को भविष्य में होने वाली उनकी उपज के लिए मार्किट उपलब्ध रहेगा जिससे बांस कृषि लाभकारी साबित होगी।
- इस वर्कशॉप में सम्मिलित प्रत्येक तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा एक माह की अवधि में 50 कृषकों को बांस कृषि करने हेतु प्रोत्साहित किया जावे जिससे यह प्रयास वास्तविक रूप से सफल हो।

श्री रमेश कुमार गुप्ता, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख ने प्रशिक्षण में सम्मिलित वन-कर्मियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र के बांस उद्यमियों से चर्चा कर SWOT Analysis करें जिससे उनकी सफलता अथवा असफलता के कारण पता लगें। इस अध्ययन से भविष्य में लगने वाले उद्योगों को इस आधार पर उचित मार्गदर्शन दिया जा सकेगा। वन बल प्रमुख ने कहा कि तकनीकी विशेषज्ञों को expo-sure विजिट्स पर राज्य में एवं राज्य के बाहर भेजा जावे जिससे वे व्यवहारिक ज्ञान अर्जित कर बांस के विशेषज्ञ बन सकें ।

इस वर्कशॉप के तकनीकी सत्र में श्री चितरंजन त्यागी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (विकास) द्वारा बांस कृषि की पद्धतियों पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसमें मुख्यतः बांस की सुरक्षा, पुष्पन के समय आग से बचाव हेतु उचित प्रबंधन, बांस की आत्मरक्षक प्रकृति आदि विषयों पर चर्चा की गई।श्री अतुल कुमार जैन, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) ने भी इस बैठक में प्रतिभागियों को अपने बहुमूल्य ज्ञान से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि शासकीय रोपणियों में वर्तमान में देसी एवं कटंग बांस के पौधे विकसित किये जा रहे हैं। प्रमुख सचिव महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में इन रोपणियों में देसी बांस के स्थान पर कटंग के साथ-साथ बल्कूआ, टुल्डा आदि को विकसित किया जावेगा।डॉ. ए.के. भट्टाचार्य, पूर्व मिशन संचालक, म. प्र. राज्य बांस मिशन ने बांस कृषि से जुड़ी तकनीकी बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण कर प्रतिभागियों को बांस की विभिन्न प्रजातियों की विशेषताएं, उनके उपयोग एवं उनका व्यावसायिक महत्व समझाया।

इस प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में डॉ. उत्तम कुमार सुबुद्धि, APCCF एवं मिशन संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन द्वारा प्रदेश में बांस क्षेत्र के विकास हेतु तकनीकी विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका की व्याख्या की गयी एवं उन्हें राज्य में उपलब्ध बांस संसाधन, बांस की प्रजातियाँ, उनके बहुतेरे उपयोग, आदि से अवगत कराया गया।

राज्य में बांस मिशन द्वारा संचालित योजनाओं के विषय में सूचित करने हेतु कार्यक्रम में सम्मिलित सभी वन-कर्मियों को मिशन द्वारा प्रकाशित प्रशिक्षण पुस्तिका प्रदान की गई। इसमें निम्नलिखित विषयों पर विस्तृत विवरण दिया गया है जिससे बांस के तकनीकी विशेषज्ञों

द्वारा प्रदेश के विभिन्न वनमण्डलों में स्थित अधिक से अधिक कृषकों एवं उद्यमियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके :-

- बांस का परिचय
- बांस की प्रमुख commercially important प्रजातियों की पहचान एवं उपयोग
- राज्य में संचालित कृषकों एवं उद्यमियों हेतु राष्ट्रीय बांस मिशन योजना का विवरण
- बांस कृषि से अनुमानित लाभ-लागत
- बांस कृषि से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी (बांस रोपण, प्रबंधन एवं विदोहन)
- प्रदेश में प्रमुख बांस किसानों की सूची (इच्छुक किसानों के मार्गदर्शन हेतु)
- कृषकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण पौधों के क्रय हेतु मिशन द्वारा प्रमाणीकृत रोपणियों एवं भारत सरकार द्वारा NCS-TCP प्रमाण-पत्र प्राप्त टिश्यू कल्चर प्रयोगशालाओं की सूची
- प्रदेश में बांस क्रय के विकल्प एवं बांस ट्रेडर्स की सूची।

सत्र में सम्मिलित बांस के सफल किसानों द्वारा बांस कृषि में होने वाली लागत और उससे प्राप्त लाभ पर चर्चा की गयी। उनके द्वारा बांस के साथ अंतरवर्ती फसलों का चयन एवं उससे उत्पन्न होने वाले लाभ भी बताए गए। ऐसे ही एक अनुभव को साझा करते हुए बांस के एक प्रमुख किसान श्री सरदार भायरे द्वारा बताया गया कि टिड्डी दल के हमले के दौरान सभी टिड्डियां बांस की ओर आकर्षित हो गई जिससे मूंग की फसल को कोई हानि नहीं हुई। उनके द्वारा यह भी बताया गया की बांस के खेत के आस-पास पराली जलाने से उसमें आग लगने का खतरा रहता है। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये।

इस प्रशिक्षण सत्र के परिणामस्वररूप प्रतिभागियों में बांस क्षेत्र के विकास हेतु कार्य करने की नई ऊर्जा, रुचि एवं उत्सुकता उत्पन्न हुई। सत्र के समापन उपरान्त प्रतिभागियों से इस प्रशिक्षण कार्यशाला पर सकारात्मक फीडबैक प्राप्त हुए। इनमें बांस क्षेत्र के विकास हेतु वनमण्डल स्तर पर अमल किये जाने वाले कई अहम सुझाव भी प्राप्त हुए जिन पर मिशन द्वारा उचित कार्यवाही की जा रही है। मिशन द्वारा इन तकनीकी विशेषज्ञों का एक whatsapp ग्रुप बनाया गया है जिसपर समय-समय पर बांस से सम्बंधित इनके द्वारा चाही गई जानकारी प्रदान की जा रही है। मिशन इस प्रकार की कार्यशालाओं के नियमित आयोजन को सुनिश्चित कर बांस तकनीकी विशेषज्ञों के इस नेटवर्क की वृद्धि एवं विस्तार की ओर प्रयासरत है।

Earth Hour day Awareness Program -2022

इस दिन दुनियाभर में लोग एक घंटे के लिए बिजली की खपत को बंद कर देते हैं। इस कारण इसे अर्थ आवर कहा जाता है। यह कार्यक्रम दुनिया के कुछ चुनिंदा जमीनी कार्यक्रमों में से एक है जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। इस साल अर्थ आवर दिनांक 26.03.2022 को रात्रि 8.30 बजे से 9.30 बजे तक मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल द्वारा डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. फॉर नेचर के सहयोग से डॉ. अतुल श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव के मार्गदर्शन में दिनांक 26.03.2022 को अर्थ आवर के अवसर पर भोपाल में डी.बी. मॉल में निर्धारित समय 8.30-9.30 रात्रि एक घंटे के लिए जनसमुदाय एवं स्थानीय लोगों द्वारा अनुपयोगी बिजली के उपयोग को सीमित किये जाने के उद्देश्य से बिजली बंद की गयी। इस आंदोलन का उद्देश्य उपयोगी बिजली की खपत को कम करना होता है। कार्यक्रम में पुलिस बैंड द्वारा देश भक्ति संगीत की शानदार प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में डॉ. बकुल लाड़, सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, श्रीमती संगीता सक्सेना, संचालक, डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. फॉर नेचर, बोर्ड के तकनीकी विशेषज्ञ, डॉ. कुनिका सिलोदिया, डॉ. गौरव सिंह, विजेश हरियाले, विवेक पांडेय, शुभम एवं शिवानी शर्मा उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड डॉ. बकुल लाड, सहायक सदस्य सचिव, द्वारा अर्थ आवर के अवसर पर दिनांक 26.03.2022 को रात्रि 8.30 बजे से 9.30 बजे अर्थ आवर विषय पर व्याख्यान दिया गया।

विश्व पर्यावरण दिवस पर वन विभाग द्वारा राज्य में आयोजित विभिन्न गतिविधियां

1. नर्मदा जलग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान 2022

वृक्षारोपण संकल्प दिवस, 5 जून 2022-नर्मदा नदी का उद्गम मैकल पर्वत पर अमरकंटक स्थित एक कुंड से होता है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1057 मीटर है। नर्मदा नदी मध्यप्रदेश की जीवन रेखा है, इसलिए प्रदेश के आमजन इसे मां नर्मदा के नाम से संबोधित करते हैं। नर्मदा घाटी में निवास करने वाले लोगों की सम्पन्नता का आधार नर्मदा से प्राप्त होने वाला अविरल एवं निर्मल जल है। मध्यप्रदेश में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि नर्मदा नदी की अविरल और निर्मल धारा अनंत काल तक प्रवाहित होती रहे। नमर्दा नदी उद्गम स्थल अमरकंटक से पश्चिमी दिशा में बहते हुए अरब की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है जिसमें से मध्यप्रदेश राज्य की सीमा तक नदी की लंबाई लगभग 1079 किलोमीटर है। नर्मदा के जल का स्रोत उत्तर भारत की नदियों की तरह ग्लेशियर पर आधारित नहीं है, बल्कि नर्मदा के जल का मुख्य स्रोत जलग्रहण क्षेत्र में स्थित वन क्षेत्र है। नर्मदा नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र 98796 वर्ग किलोमीटर है जिसमें से 85149 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मध्यप्रदेश में स्थित है, जो नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 87% है। मध्यप्रदेश में स्थित जलग्रहण क्षेत्र में 32400 वर्ग किलोमीटर, अर्थात् 38% वन क्षेत्र है। अन्य क्षेत्रों में किए जाने वाले विभिन्न उपचारों के अलावा नर्मदा को अनंत काल तक अविरल और

निर्मल बनाए रखने के लिए जलग्रहण क्षेत्र में स्थित वन क्षेत्रों का संरक्षण एवं सुधार अत्यंत आवश्यक है। नदी के जल की मात्रा एवं गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए वानिकी आधारित पहल की गई है जिसमें नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को संरिक्षत करने के लिए स्थानीय समुदायों के सहयोग से जलग्रहण क्षेत्र में वृक्ष आच्छादन का कार्य किया जा रहा है। वृक्षारोपण का दीर्घकालीन संवहनीय प्रबंधन वन समितियों के लिए तैयार की गयी माइक्रोप्लान के अनुसार किया जाएगा।

राज्य शासन के संकल्प के अनुसार वृक्षारोपण से प्राप्त होने वाली समस्त वनोपज पर स्थानीय ग्रामवासियों का अधिकार होगा। सहभागी वन प्रबंधन से वृक्ष आच्छादन के साथ-साथ स्थानीय समुदायों की आजीविका भी सुदृढ़ होगी। आम लोगों के बीच वनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नर्मदा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य को अभियान के रूप में संपादित करने के लिए विश्व पयार्वरण दिवस, 5 जून 2022 को ''वृक्षारोपण संकल्प दिवस'' के रूप में मनाया जा रहा है। इस हेतु निम्न कायर्वाही सुनिश्चित की जाएगी -

1. स्थानीय नागिरकों, स्वयंसेवी संस्थाओं, समाजसेवियों, शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की सहभागिता से प्रत्येक वनमंडल में विश्व पयार्वरण दिवस, 5 जून 2022 को नर्मदा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में 'वृक्षारोपण संकल्प दिवस' के रूप में मनाया जाएगा।

2. नमर्दा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में 494 ग्रामों में वन समितियों के माध्यम से कुल 18406 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 1.32 करोड़ पौधों का रोपण किया जाना है। सभी जिलों में अधिकारियों एवं स्थानीय वन समितयों द्वारा ''वृक्षारोपण संकल्प दिवस'' पर संकल्प लिया जाएगा कि वह नर्मदा की जल धारा को अविरल एवं निर्मल बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण की हमेशा रक्षा करेंगे तथा वन क्षेत्र का संवहनीय प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रदेश के नागिरकों एवं वृक्षारोपण अभियान के भागीदारों को जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न विभागीय एवं गैर-विभागीय योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2022 की वर्षा ऋतु में वनभूमियों पर किए जा रहे सभी वृक्षारोपणों को 'वृक्षारोपण मॉनीटरिंग सिस्टम' पर पंजीकृत कर क्षेत्र के पॉलीगन की KML फ़ाइल को अपलोड किया जाएगा। इस अभियान के तहत 31 जुलाई तक किए गए वृक्षारोपणों के संबंध में जानकारी मय फोटोग्राफ विभागीय पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।

4. भूमि संरक्षण के साथ-साथ कृषकों की आमदनी बढ़ाने के लिए नदी के किनारों पर स्थित ढलानी एवं भू-क्षरण के लिए संवेदनशील कृषकों की भूमियों पर भी बांस मिशन के माध्यम से बांस का रोपण किया जा सकता है। इस हेतु कृषि एवं उद्यानिकी विभागों तथा वैज्ञानिक संस्थानों के बीच समन्वय एवं अभिसरण से कृषकों को जानकारी देने एवं वानिकी समाधानों को लागू करने के लिए पहल की जाए।

5. वृक्षारोपण कार्य का शुभारम्भ स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप वांछित वर्षा एवं मिट्टी में नमी होने के बाद ही प्रारम्भ किया जाएगा। वृक्षारोपणों की दूरगामी सुरक्षा एवं प्रबंधन हेतु स्थानीय समुदायों को नर्मदा संरक्षण, जल प्रबंधन के अलावा राज्य शासन के जनभागीदारी के संकल्प-2001 के अनुसार वृक्षारोपण से स्थानीय समुदायों को होने वाले लाभों के संबंध में भी अवगत कराया जाएगा। आम नागिरकों की भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु कार्यक्रम का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

ग्राम वन समिति नयेगाँव, परिक्षेत्र-डिंडोरी, वनमंडल-डिंडोरी को वनोपज की राशि का भुगतान

वर्ष 2010 में समिति के वन क्षेत्र में मनरेगा योजना के तहत 50 हेक्टेयर बांस का रोपण किया गया था। वृक्षारोपण क्षेत्र के प्रबंधन के लिए माइक्रोप्लान तैयार किया गया तथा बांस का प्रबंधन प्रारम्भ किया गया। माइक्रोप्लान में बांस के क्षेत्र को 12.5 हेक्टेयर के चार भागों में विभक्त करके चार वर्षीय प्रबंधन चक्र बनाया गया है। समिति के सदस्यों द्वारा बालाघाट से प्रशिक्षण प्राप्त करके बांस के फेंसिंग पोल बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। समिति द्वारा विदोहित बांस के 8487 फेंसिंग पोल वन विभाग को निर्धारित दर ₹ 106/- प्रति पोल से सप्लाई किए गए हैं तथा 19 टन बाँस राशि ₹ 77000/ में ओरिएंट पेपर मिल को बिक्री किया गया है। वन विभाग को सप्लाई किए गए फेंसिंग पोल्स का

भुगतान राशि रुपए 9 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी के कर-कमलों से 5 जून 2022 को भोपाल में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष श्री लाल सिंह एवं सचिव सुश्री विमला व राम मरावी को प्रदाय किया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है की गत एक दशक में डिंडोरी जिले की 145 ग्राम वन समितियों द्वारा 39101 हे. बिगड़े वन क्षेत्र को अच्छे वन क्षेत्र में परिवर्तित कर एक मिसाल कायम की गयी है। स्थानीय समुदायों की आजीविकाओं पर आधारित केंद्रित वन संरक्षण का यह उत्कृष्ट उदाहरण है।

2. विश्व पर्यावरण दिवस पर पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान :

5 जून 2022, विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी अंतर्गत समस्त 09 कोर एवम् बफर परिक्षेत्रों में उत्साहपूर्वक आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर समस्त पर्यटन द्वारों में जंगल सफारी हेतु पधारे पर्यटकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने एवम् उन्हें इस कार्य से जोड़ने हेतु नीम प्रजाति के 200 पौधे उपहार स्वरूप पार्क प्रबंधन द्वारा भेंट किये गये। नीम के पौधे में औषधीय गुण होने के साथ-साथ यह वायुमण्डल की वायु को शुद्ध भी करता है एवम् जब पर्यटक अपने-अपने गृह नगरों में जाकर अपने घर आंगन में इस पौधे को रोपित कर इसका संरक्षण करेंगे तो निश्चित ही पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी की स्मृति उन्हें इस बाबत प्रेरित करेगी। पेंच प्रबंधन द्वारा ऐसे पर्यटकों के लिये जो कि पौधा दूर तक परिवहन करने में असमर्थ हैं, उन्हें पौधा रोपित करने हेतु परिक्षेत्र खवासा के वन चेतना केंद्र एवम् रुखड़ तथा मासुरनाला पर्यटन द्वार के समीप प्रांगण में पौधा रोपित करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।

इसके अतिरिक्त पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के सभी 9 कोर एवम् बफर परिक्षेत्रों में 167 पेट्रोलिगं केम्प, वनरक्षक नाका, बेरियर, कार्यालय केम्पस, परिक्षेत्र सहायक निवास एवं अन्य भवनों में 1169 फलदार पौधों एवं 50 बांस के पौधों का रोपण किया गया है। आम, कटहल, मुनगा, नींबू, करौंदा प्रजाति के फलदार प्रजाति के पौधों के रोपण का उद्देश्य दूरस्थ वन क्षेत्र में स्थित केम्पों में रहने वाले श्रमिकों एवम् वन कर्मचारियों को उनके निवास स्थल पर ही पौष्टिक फल एवम् सब्जियां उपलब्ध कराना है। इस प्रकार पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी अंतर्गत कुल 1419 पौधों का रोपण एवम् वितरण विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में किया गया।

3. विश्व पर्यावरण दिवस पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में जन चेतना कार्यक्रम

इस वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत ही 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जन मानस में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में जन चेतना कार्यक्रम का आयोजन वन विहार, जैवविविधता बोर्ड एवं किताबखाना एन.जी.ओ. द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण प्रेमियों एवं छात्र/छात्राओं हेतु पक्षी अवलोकन शिविर का आयोजन किया गया तथा विद्यार्थियों हेतु भाषण प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता एवं खुला प्रश्न मंच प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय "Living sustainably in harmony with nature" का समाज में संदेश प्रसारित करना है तथा कैम्पेन का स्लोगन "Only One Earth" रखा गया है। उक्त अवसर पर म.प्र. जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव एवं प्रधान मुख्य वन सरंक्षक डॉ. अतुल श्रीवास्तव, संचालक वन विहार श्री एच.सी. गुप्ता, उप वन संरक्षक एवं सहायक संचालक श्री ए.के. जैन, सहायक सदस्य सचिव जैवविविधता बोर्ड डॉ. बकुल लाड़ तथा वन विहार एवं जैवविविधता बोर्ड के अधिकारी/ कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों/ महाविद्यालय/ एन.एस.एस. के लगभग 225 विद्यार्थियों तथा लगभग 75 पर्यावरण प्रेमियों ने भाग लिया। श्री ए.के. जैन, सहायक संचालक द्वारा कार्यक्रम की विषय वस्तु पर प्रकाश डाला गया तथा कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को पर्यावरण संरक्षण करने एवं प्रदूषण न फैलाने हेतु शपथ दिलाई गई। खुला प्रश्न मंच का संचालन डॉ. सुदेश वाघमारे से.नि. उप वनसंरक्षक द्वारा किया गया एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा 20 विद्यार्थियों/ पर्यावरण प्रेमियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों को वन विहार की जैवविविधता से भी परिचय कराया गया। साथ ही प्रतिभागियों को भोपाल बर्ड्स की डॉ. संगीता राजगीर एवं मो. खालिक द्वारा पक्षी दर्शन कराया गया एवं वन विहार में पाये जाने वाले विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की जानकारी दी गई इसमें अजीम प्रेमजी फाउंडेशन संस्था के सदस्यों द्वारा भी भाग लिया गया।

कार्यक्रम के अंत में श्री ए.के. जैन, उप वनसंरक्षक द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों, शिक्षकों, अभिभावकों, पर्यावरण प्रेमियों तथा उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आभार व्यक्त किया गया। दोनों प्रवेश द्वारों पर पर्यटकों के मध्य संदेश प्रसारित हेतु पर्यावरण फ्रेंडली बेनर लगाये गये तथा आगंतुक पर्यटकों को पर्यावरण महत्व एवं प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सहभागिता करने हेतु सहयोग मांगा गया। इस अवसर पर अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक रूप से पौधारोपण का कार्य भी किया गया।

"एक जिला, एक उत्पाद": बांस, वन वृत्त, रीवा

दिनांक 10.02.2022 को वन वृत्त, रीवा अंतर्गत पर्यावरण विकास केन्द्र में तक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बांस उत्पादन से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप श्री अशोक बर्णवाल भा.व.से. प्रमुख सचिव म.प्र. भोपाल, श्री चितरंजन त्यागी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (विकास) म.प्र. भोपाल, श्री उत्तम कुमार सुबुद्धि अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य बांस मिशन भोपाल, श्री आनन्द कुमार सिंह भा.व.से. मुख्य वनसंरक्षक रीवा वृत्त रीवा, श्री राजीव मिश्रा भा.व.से. मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी वन वृत्त रीवा, श्री मनोज पुष्प भा.व.से. कलेक्टर जिला रीवा, श्री मधु वी.राज भा.व.से. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली, श्री चन्द्रशेखर सिंह भा.व.से. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रीवा, श्री विपिन कुमार पटेल भा.व.से. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल, सतना, उपसंचालक कृषि यू.पी. बागरी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में रीवा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बांस रोपण हेतु इच्छुक 171 कृषक भी शामिल हुए। उपस्थित कृषकों एवं व्यापारियों को बांस के उत्पादन हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत रीवा जिले में कृषि क्षेत्र में बांस वृक्षारोपण हेतु रकबा 500 हे. पौधा संख्या 02 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

श्री उत्तम कुमार सुबुद्धि, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य बांस मिशन भोपाल द्वारा बांस की विभिन्न प्रजातियों की जानकारी दी गई। कृषकों को राज्य बांस मिशन के बारे में बताया गया उन्होंने बांस की खेती के लिये तैयारियों, लागतों तथा बिक्री की संभावनाओं तथा बांस के व्यावसायिक उत्पादन के विभिन्न पक्षों की विस्तार से जानकारी दी। बांस के उत्पादन, विदोहन एवं व्यापार से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया गया।

श्री रमेश कुमार गुप्ता भा.व.से. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल द्वारा बताया गया कि बांस की खेती नहीं बल्कि व्यावसायिक उत्पादन किया जाना चाहिए। इसे व्यवसाय के रूप में अपनाकर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं जो किसान बांस की सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं। उनके यहां अन्य किसानों का भ्रमण कराकर बांस की खेती के अच्छे अनुभव लिये जा सकते हैं तथा किसानों से बांस की खेती करने हेतु किसानों को प्रेरित किया गया। परिचर्चा के दौरान किसानों ने अपने अनुभव साझा किये तथा

बांस उत्पादन में आने वाली कठिनाई एवं आवश्यक सुझावों के बारे में अवगत कराया। कृषकों की बांस उत्पादन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान उपस्थित अधिकारियों द्वारा किया गया।

कार्यशाला में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि रीवा जिला मुंबई, बनारस औद्योगिक कॉरिडोर का भाग है। यहां अन्य उद्योगों के साथ बांस उद्योग की प्रबल संभावना है। किसान बांस की खेती को अपनाकर अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं। बांस की खेती के लिये वन विभाग से पौधे तथा तकनीकी मार्गदर्शन दिया जायेगा। किसानों को बांस की बिक्री के लिए भी हर संभव सहायता दी जायेगी। एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल बांस रोपण को अपनाकर जिले में आर्थिक विकास का नया अध्याय लिखा जा सकता है।

परिचर्चा उपरांत श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव वन द्वारा बताया गया कि कम खर्च में अधिक लाभ देता है बांस, रीवा में इसकी खेती कर रीवा को आदर्श बनायें। जिले में बांस रोपण की अपार संभावनाएं हैं एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल बांस उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला से चर्चा करते हुए प्रमुख सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि रीवा जिले में 5 से 10 हजार एकड़ में बांस की खेती की जा सकती है। बांस की खेती परंपरागत खेती की तुलना में कम लागत तथा कम रिस्क पर अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है।

अच्छी किस्म का बांस रोपित करने के बाद 5वें वर्ष से लगभग 40 वर्षों तक लगातार लाभ मिलता रहता है। एक बार बांस रोपित करने तथा 02 वर्षों तक देखभाल के अलावा इसमें किसी तरह का खर्च नहीं आता है। आगामी 20 वर्षों तक बांस की बहुत अधिक मांग रहेगी। लकड़ी के स्थान पर अब बांस के उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है।

प्रमुख सचिव वन श्री अशोक बर्णवाल, ने कहा कि परंपरागत खेती में आने वाले खर्च का हिसाब-किताब लगाने के बाद किसान बांस की खेती को अपनाएं जब बड़े क्षेत्र में बांस का रोपण होगा तभी अधिक लाभ मिलेगा।

निजी कंपनी वाले 02 रुपये 55 पैसे प्रति किलो की दर से बांस खरीदने का एग्रीमेंट कर रहे हैं। बांस की खेती में मौसम का असर नहीं पड़ता है। बांस, पीपल के बाद सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। इमारती लकड़ी के वृक्ष 25 से 30 साल में तैयार होते हैं, जबकि बांस 5 से 7 साल में तैयार हो जाता है एवं लगातार उत्पादन देता रहता है। कार्यशाला के बाद अधिकारियों ने परिसर में लगाई गई बांस उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

बांस उत्पादन से जुड़े किसानों तथा व्यावसायियों, आर्टिस्ट एग्रोटेक के दीपक खरे, देवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, मो. रिजवी, इस्लाम खान, शिवेन्द्र मोहन तिवारी, अजय सिंह तथा अन्य किसानों ने अपने विचार व्यक्त किये। कार्यशाला में अतिथियों को बांस से बनी कलाकृकियों भेंट की गईं।

म.प्र. राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ एवं एम.एफ.पी- पार्क

प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवॉर्ड 2022 से सम्मानित

देश में स्कॉच द्वारा विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को अवॉर्ड प्रदान किये जाते हैं। म.प्र. राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित भोपाल एवं लघुवनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी- पार्क) बरखेड़ा पठानी को देश के प्रतिष्ठित स्कॉच अवॉर्ड 2022 अंतर्गत राज्य शासन श्रेणी में सिल्वर अवॉर्ड प्राप्त हुए हैं।

लघुवनोपज संघ को, "Development of public awareness about herbal product for health security" एवं एम.एफ.पी- पार्क को यह अवॉर्ड " "Vocal for local" (Sustainable development of rural livelihood generation) के लिये सिल्वर अवॉर्ड प्रदान किये गये हैं।

डॉ. कुँवर विजय शाह जी माननीय वन मंत्री म.प्र. को लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री पुष्कर सिंह द्वारा प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवॉर्ड 2022 की ट्रॉफियां मंत्रालय में भेंट की गई।

इस अवसर पर माननीय वन मंत्री ने म.प्र. राज्य लघुवनोपज संघ एवं लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी- पार्क) को प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवॉर्ड 2022 प्राप्त हाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर वन विभाग म.प्र. के प्रमुख सचिव श्री अशोक बर्णवाल, वन बल प्रमुख एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री आर.के. गुप्ता, डॉ. दिलीप कुमार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एवं एम.एफ.पी- पार्क उपस्थित रहे। लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री पुष्कर सिंह ने सिल्वर अवॉर्ड प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी। डॉ. दिलीप कुमार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.एफ.पी- पार्क ने सिल्वर अवॉर्ड प्राप्त होने पर कहा कि यह हम सबके लिये प्रेरणादायी और उत्साहवर्धक है।

लघु वनोपज सहकारी संघ, एमएफपी पार्क भोपाल को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2022

भोपाल (वार्ता)।

वन मंत्री डॉ विजय शाह ने मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ एवं लघु वनोपज प्र-संस्करण एवं अनुसंधान केंद्र-एमएफपी पार्क-बरखेड़ा पठानी भोपाल को देश के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2022 के सिल्वर वर्ग में प्रथम आने पर बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं।

प्रयास करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव वन अशोक वर्णवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख आर.के. गुप्ता एवं एमएफपी पार्क के सीईओ डॉ. दिलीप कुमार उपस्थित थे।

स्व. माथुर की जयंती पर प्रदेश अध्यक्ष ने किए श्रद्धासुमन अर्पित

अखिल भारतीय बाघ आंकलन-2022

मध्यप्रदेश ने वर्ष 2018 में हुए बाघ आंकलन में 526 बाघों के साथ बाघ प्रदेश का खोया हुआ दर्जा पुन: हासिल किया था। बाघ प्रदेश के दर्जे को कायम रखने हेतु अखिल भारतीय बाघ आंकलन 2022 के विभिन्न चरणों की कार्यवाही प्रचलित है। जिसमें विभाग के अधिकारी/कर्मचारी बढ़-चढ़कर योगदान दे रहे हैं। अखिल भारतीय बाघ आंकलन अंतर्गत प्रदेश स्तर पर वनमंडल वार चयनित हुए लगभग 300 मास्टर ट्रेनर को राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा माह अगस्त-सितम्बर 2021 में प्रशिक्षण दिया गया तथा इन्हीं कर्मचारियों द्वारा अपने क्षेत्र के वनमंडल/परिक्षेत्र स्तर पर प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। कनिष्ठ से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

मध्यप्रदेश देश की सबसे अधिक वनबीटों वाला राज्य है यहां 8826 वन बीटें हैं। प्रदेश की इन्हीं वनबीटों में बाघ, तेंदुआ तथा अन्य वन्यप्राणियों की उपस्थिति के उद्देश्य से अखिल भारतीय बाघ आंकलन-2022 का फेस-1 डाटा कलेक्शन कार्य दिनांक 17.11.2021 से शुरू हो गया है जिसमें प्रदेश की वनबीटों को चार भागों में विभाजित करते हुए डाटा कलेक्शन कार्य किया गया है। यदि किसी कारणवश किन्हीं बीटों में फेस-1 डाटा कलेक्शन कार्य पूर्ण नहीं हो पाया तो उन समस्त बीटों का डाटा कलेक्शन कार्य पंचम उपचरण दिनांक 18.01.2022 से 24.01.2022 के मध्य सम्पादित किया गया। प्रथम तीन चरण में प्रदेश के समस्त 16 वनवृत्तों में फेस-1 डाटा कलेक्शन कार्य 21.12.2021 को सम्पादित किया गया है तथा चतुर्थ चरण दिनांक 05.01.2022 से 11.01.2022 तक प्रदेश के टाइगर रिज़र्वों, माधव व कूनो राष्ट्रीय उद्यान तथा औबेदुल्लागंज वनमंडल में सम्पादित किया गया है। इसी के साथ ही प्रदेश में फेस-3 कैमरा ट्रेपिंग का कार्य भी प्रगति पर है। वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण विशेष तौर पर अखिल भारतीय बाघ आंकलन-2022 में बढ़-चढ़कर योगदान दिया गया है। निश्चित ही पूर्व वर्ष की भांति ही प्रदेश अखिल भारतीय बाघ आंकलन-2022 में पुन: नया कीर्तिमान हासिल करेगा।

73वां गणतंत्र दिवस समारोह : प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख रमेश कुमार गुप्ता द्वारा ध्वजारोहण एवं पुरस्कार वितरण

गणतंत्र दिवस समारोह - 2022
आज़ादी का अमृत महोत्सव

‘Collarwali Supermom’ the legendary tigress of Pench Tiger Riserve

Badimada Tigress of Pench Tiger Reserve has given birth 4 cub, 2 males and 2 females in first week of September 2005 at Arjalmatta, Beat Bison. One female cub along with three other cubs was regularly monitored by using elephants. This female cub was radio collared on 11th March 2008. After non functioning of radio collar, she was again radio collared on 9th Jan 2010. This tigress was becomes famous as “Collarwali” or T15 Tigress.

Collarwali Tigress established her territory in the prime area of her mother’s range. The natal area of this Tigress in between may 2006 and June 2007 was found 23.9 km^2 area. She occupied main prime Cheetal area in and around Alikatta.

Collarwali first littered in May 2008 going birth to 3 beautiful cubs in Bhola Gufa area (Comptt. no. 585) of Kala Pahad, Beat Alikatta, Range Karmajhiri. These cubs could not last long and succumbed to adverse conditions and also to the inexperience of being mother first time within one and half months.

Collarwali tigress has given second litter on October 08 at to lantana no. 2 giving birth 4 cubs, 3 female and 1 male. All these 4 cubs raised to adulthood.

Collarwali tigress has given her third litter on October 23, 2010 surprisingly 5 cubs, 4 female and 1 male, at lantana no. 2. All survived to adulthood.

Collarwali tigress has given her fourth litter 3 cubs, 1 male, 2 female in May 2012 at Bhalu Gufa, Kala Pahad out of which 1 male and 1 female survived and rose to adulthood.

She has given her fifth litter on October 2013 of producing 3 male cubs at Khala Majhar (Raiyakassa comptt. no. 586) beat Alikatta. All 3 cubs rose to adulthood.

Collarwali Tigress has 6 litter birth given 4 cubs on March 2015 at near 7 no. hand pump, comptt. no. 587 beat Bison Beat.

Collarwali has given 7th litter 3 cubs, all male at Mahadeo Ghat Tapu, Comptt. 587, beat Bison.

Now she has given record time 8th litter at Lantana no. 1, Compartment No. 585, Beat Alikatta.

Looking to all factors, we can elaborate some facts about collarwali Tigress (T15).

Collarwali Tigress (T15) was born in the 1st week of Sept 2005 and her is age in 13 years 4 months at the time of 8th litter. She has given 1st litter in May 2008 which could not survived. On the same year, in October 2008, she has gives birth 4 cubs. Later on, she has given 6 litter more including the latest one in 27th December 2018 becoming Supermom. Since 1st litter was lost very early within one and half month, we can consider her actual breeding duration from October 2008 to December 2018 i.e. 10 years 2 months. She has taken sometimes less than one and half years and sometimes upto 2 years. Except the last litter (2 year 19 days). Average time taken from one litter to another 1.45 years. Out of 1st 7 litters, she has gives birth to 14 male and 11 female cubs addling 25 cubs, out of which 13 males and 08 females were survived and raised to adulthood. Survival percentage upto 7th litter is 84% which is great under any parameters. Last 8th litter 4 cubs are 1 month 10 days old cub as on 6th February 2019.

शहरी क्षेत्र में वृक्षारोपण की दिशा में एक सफल प्रयास औद्योगिक क्षेत्र, देवास रोड पर मियावाकी तकनीक से वृक्षारोपण

भीतरी, भैरवगढ़ रोड उज्जैन में मियावाकी पद्धत्ति से वृक्षारोपण करने के उपरांत अपार सफलता प्राप्त हुई। उक्त सफलता को ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसे लक्ष्य को चुना गया जहां कार्बन डाईऑक्साइड का अधिक उत्सर्जन होता था।

औद्योगिक क्षेत्र देवास रोड उज्जैन में औद्योगिक फैक्ट्रियों के मध्य 0.25 हेक्टेयर क्षेत्र को मियावाकी पद्धति अनुसार रोपण हेतु चुना गया एवं वर्ष 2021 में कुल 3000 पौधों का मियावाकी पद्धति से रोपण किया गया, जिसमें नियमानुसार क्षेत्र की सफाई, जुताई, समतलीकरण का कार्य कर पौधा रोपण कराया गया।

इस पद्धति की प्रक्रिया :-

1. स्थानीय प्रजातियों का चयन एवं मिट्टी का परीक्षण।
2. क्षेत्र सफाई कार्य।
3. जमीन में तीन फीट गहरी जुताई, जैविक खाद, कोकोपिट, घास, वर्मी कम्पोस्ट आदि के मिश्रण मिलाकर गड्ढे के ऊपर मिट्टी डालकर परत बनाना।
4. दो से पाँच पौधे प्रति वर्ग मीटर की दूरी पर रोपण पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत एवं चौथी परत में किया जाता है।
5. अलग-अलग प्रकार के पौधे एक साथ नहीं रोपकर थोड़े-थोड़े दिन में रोपे जाते हैं।
6. यह पूरी प्रक्रिया 2 से 3 सप्ताह में पूरी की जाती है।
7. तीन वर्ष तक सिंचाई एवं रखरखाव कार्य करना।

सर्वे कार्य

क्षेत्र सफाई

जुताई एवं घास व पत्ते डालने के पश्चात् समतलीकरण कार्य

रोपित की गई प्रजातियां

S.No.	Lower Layer		Middle Layer		Co-dominant		Dominant	
	प्रजाति	संख्या	प्रजाति	संख्या	प्रजाति	संख्या	प्रजाति	संख्या
1	जामफल	37	लसौड़ा	12	बेलपत्र	20	इमली	270
2	सीताफल	15	पुत्रंजीवा	10	मोलश्री	25	शीशम	100
3	गुड़हल	62	कुल्लू	15	खिरनी	25	महुआ	125
4	अंजन	25	अचार	12	पाखर	25	कुसुम	100
5	गुग्गल	12	कपोक	75	बादाम	25	बीजा	25
6	नींबू	75	कचनार	77	पेल्टाफार्म	100	बहेड़ा	150
7	बोगन वेलिया	50	कदम	15	जामुन	24	अर्जून	150
8	कष्टार	20	पारस-पीपल	87	फाईकस	24	बरगद	20
9	सप्तपर्णी	20	जेकेरेन्डा	15	शमी	20	पीपल	50
10	अस्तरा	20	करंज	125	अमलतास	25	सागौन	75
11	वेरीगेटेड पा.पीपल	20	खैर	75	शहतूत	75	नीम	75
12			कनेर	90	खमेर	27		
13			गधापलास	20	जं. जलेबी	100		
14			पापुलर	37	आंवला	50		
15			कटहल	87	सफेद खैर	90		
16			बैर	37				
17			सीरस	60				
योग	**11 प्रजाति**	**356**	**17 प्रजाति**	**849**	**14 प्रजाति**	**655**	**11 प्रजाति**	**1140**

कुल प्रजाति संख्या - 53 प्रजाति, कुल पौधे संख्या - 3000 पौधे

गड्ढे खुदाई एवं पौधा जमाई कार्य

पौधा रोपण उपरांत निरीक्षण

माह अप्रैल 2022 में वृक्षारोपण की ग्रोथ

जनजातीय कौशल विकास क्षेत्र में कान्हा प्रबंधन की नई पहल

कान्हा में बैगा आभूषण

मध्य भारत के उच्च पठारों के जंगलों में रहने वाले "विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह'' - बैगा अपने समुदाय में कौशल के अनेक नायाब खजाने को छुपाये हुये है। इसी में से एक है अपने लिये बनाये जाने वाले अत्यंत सुंदर आभूषण जो कि महिलायें त्योहारों एवं विवाह समारोह में धारण करती हैं। इन्हें स्थानीय रूप से "मुंगादाना'' एवं ''मोतीदाना'' कहते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व के आस-पास रहने वाले बैगा जनजातीय की इसी कौशल को बढ़ा कर उन्हें आमदनी का एक नया स्रोत देने हेतु कान्हा प्रबंधन ने "दी लास्ट विल्डरनेश फाउंडेशन'' की सहायता से एक पहल की है।

इसके लिये ग्राम बांधाटोला की 12, झगड़ाटोला की 10, चिचरिंगपुर की 5 एवं खुरसीपार की 1 महिलाओं को प्रेरित कर दी लास्ट विल्डरनेश फाउंडेशन की सहायता से आभूषण बनाने के कौशल को बढ़ावा दिया गया है। उन्हें आभूषण बनाने हेतु विभिन्न सामग्री जैसे मूंगा, मोती, तांत आदि बुनियादी सामग्री प्रदाय की गयी तथा तैयार किये गये आभूषण प्राप्त कर उसे विक्रय की सुविधा प्रदाय की गयी है। बनाये गये आभूषणों को कान्हा वर्कर्स सोसायटी के शोविनियर शॉप्स में रखकर विक्रय किया जा रहा है इसके अतिरिक्त दी लास्ट विल्डरनेश फाउंडेशन की सहायता से इसे पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलौर आदि के मेले में रखकर तथा ऑनलाइन शापिंग साइट्स अमेजान में विक्रय हेतु उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में इस तरह विक्रय पद्धति अपनाकर इन ग्राम की महिलाओं को अंशकालिक कार्य करने पर औसतन प्रतिदिन रु. 350-500 तक आय हो रही है। इस गतिविधि के प्रारंभ हो जाने से इस समुदाय का आस-पास के जंगलों पर निर्भरता में कमी आयी है।

विश्व गौरैया दिवस जागरूकता कार्यक्रम-2022

गौरैया पैसेरिडी परिवार की सदस्य है। यह पक्षी मानव आबादी के आस-पास पाया जाता है तथा स्वस्थ पर्यावरण का सूचक है। वर्ष 1970 के पश्चात् इनकी संख्या में निरंतर कमी देखी गई है। इनकी संख्या में कमी आने के प्रमुख कारण नीड़न स्थान की कमी, लार्वो की कमी, मोबाइल तरंगें, कीटनाशक, अनलेडेड पेट्रोल आदि हैं। गौरैया की घटती संख्या को देखते हुये जागरूकता लाने के उद्देश्य से वर्ष 20 मार्च 2010 से सम्पूर्ण विश्व में गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत की गई।

इस वर्ष दिनांक 20 मार्च 2022 को गौरैया दिवस के अवसर पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम भोपाल बड्र्स संस्था के सहयोग से मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड एवं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड उपस्थित रहे। कार्यक्रम में व्ही.एन.एस. नेचर सेवियर, ईको क्लब शासकीय नवीन विद्यालय एवं शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक महाविद्यालय के लगभग 122 छात्र-छात्राओं एवं सहयोगी कर्मचारियों ने भाग लिया। समस्त प्रतिभागियों को पक्षी अवलोकन एवं नेचर ट्रेल भ्रमण कराया गया।

कार्यक्रम में गौरैया पर आधारित प्रश्नोत्तरी, चित्रकला एवं कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेता प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव एवं श्री एच.सी. गुप्ता, संचालक, वन विहार द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किये गये।

विश्व गौरैया दिवस दिनांक 20.03.2022 को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में आयोजन किया गया।

बांस मिशन की कार्यशाला

वनसंरक्षक एवं पदेन वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल क्षेत्र देवास

प्राकृतिक आपदा में फसलें खराब हो जाती हैं, बांस फसल में फर्क नहीं पड़ताः वर्णवाल

एक जिला एक उत्पाद के तहत कार्यशाला में किसानों को बताए तरीके

देवास. कार्यशाला में संबोधित करते अधिकारी।

वनमण्डल क्षेत्र देवास में राज्य बांस मिशन योजना के अंतर्गत दिनांक 12 जनवरी 2022 का बांस उत्पादक कृषकों हेतु कार्यशाला का आयोजन रामश्रय होटल देवास में श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव वन म.प्र. भोपाल की अध्यक्षता में श्री रमेश कुमार गुप्ता प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल, श्री उत्तम कुमार सुबुद्धि अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य बांस मिशन भोपाल, श्रीमती कमलिका मोहंता अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उज्जैन, श्री चंद्रमौली शुक्ला, कलेक्टर जिला देवास, श्री पी.एन. मिश्रा, वनसंरक्षक देवास एवं समस्त उप वनमण्डल अधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकरी तथा बांस उत्पादक कृषकों के प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कृषि क्षेत्र में बांस रोपण हेतु बांस मिशन द्वारा दिये जाने वाली अनुदान राशि के वारे में बताया गया बांस की फसल किसी मौसम में खराब नहीं होती कम खर्च में अधिक उत्पाद लिया जा सकता है, बांस 3 मीटर दूरी पर लगायें जिसके साथ अन्य फसल भी लगा सकते हैं। खेतों एवं अन्य स्थानों पर सीमेंट के पोल से फैंसिंग के स्थान पर बांस से फैंसिंग कम खर्च में की जा सकती है, आदि के संबंध में आवश्यक जानकारी के साथ-साथ जिले के किसानों भाइयों को खेतों में मेड़ पर बांस लगाने हेतु प्रेरित किया गया है। बांस उत्पादक कृषकों को रामश्रय होटल देवास में प्रशिक्षण के पश्चात् वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बस द्वारा अन्य परिक्षेत्रों में कराये जा रहे बांस रोपण स्थलों का निरीक्षण कराया।

बांस कृषकों का प्रशिक्षण एवं कार्यशाला दिनांक 06.05.2022 एवं 09.05.2022

वनमण्डल क्षेत्र देवास के अंतर्गत वन परिक्षेत्र देवास के टोंकखुर्द सब रेंज में दिनांक 06 मई 2022 को कृषि क्षेत्र में बांस रोपण हेतु स्थानीय कृषकों की बैठक ग्राम जामुनिया एवं छायनहजाम में बांस रोपण हेतु बांस मिशन योजना अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली अनुदान की राशि एवं बांस रोपण के संबंध में समझाइश दी गई।

वनमण्डल क्षेत्र देवास के अंतर्गत वन परिक्षेत्र देवास के हाटपिपल्या सब रेंज में दिनांक 09 मई 2022 को कृषि क्षेत्र में बांस रोपण हेतु स्थानीय कृषकों की बैठक ग्राम हाटपिपल्या के आस-पास के कृषकों को बांस रोपण हेतु बांस मिशन योजना अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली अनुदान की राशि एवं बांस रोपण के संबंध में समझाइश दी गई।

बांस कृषक कार्यशाला एवं प्रशिक्षण दिनांक 10.05.2022

वनमण्डल क्षेत्रीय देवास के अंतर्गत वन परिक्षेत्र पानीगांव में दिनांक 10 मई 2022 को कृषि क्षेत्र में बांस रोपण हेतु स्थानीय कृषकों की बैठक कर बांस रोपण हेतु बांस मिशन योजना अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली अनुदान की राशि एवं बांस रोपण के संबंध में समझाइश दी गई।

वनमण्डल क्षेत्रीय देवास के अंतर्गत राज्य बांस मिशन योजना अनुसार कृषि क्षेत्र में बांस रोपण हेतु समस्त वन परिक्षेत्रों में स्थानीय अधिकारियों द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण के साथ-साथ बांस रोपण हेतु कृषकों से चर्चा कर योजना अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान की राशि के संबंध में बताया गया एवं समझाइश दी गई।

रोपणी बांसापुर वन विस्तार इकाई सीहोर

सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल

सामान्य परिचय - रोपणी बांसापुर, सीहोर जिले में बुदनी परिक्षेत्र के अंतर्गत जर्रापुर बीट के कक्ष पी-636 में राष्ट्रीय राजमार्ग-46 पर स्थित है। रोपणी की स्थापना वर्ष 2010 में पौधों की तैयारी हेतु अस्थाई तौर पर 1 हेक्टेयर में प्रारंभ की गई थी तथा वर्तमान में 4 हेक्टेयर में 7,50,000 पौधा तैयारी के साथ-साथ 300 अंकुरण बेडों में पौधा तैयारी का कार्य किया जा रहा है।

उपलब्ध संरचनायें -

कस्टमर विजिटर सेंटर

लेबर हट -2

मिस्ट चेम्बर

वर्मी कम्पोस्ट यूनिट

ग्रीन नेट हाउस

वर्ष 2022 हेतु उपलब्ध पौधे -

1.	6397 लोकवानिकी मद-	4,25,000 पौधा
2.	कैम्पा मद -	2,50,000 पौधा
3.	ग्रीन इंडिया मिशन मद -	75,000 पौधा
योग		**7,50,000 पौधा**

सशुल्क विक्रित पौधों से प्राप्त राजस्व - 3,00,000 रुपये

उच्च तकनीक रोपणी - बांसापुर में सामान्य पौधा तैयारी से 4000 रूट ट्रेनरों की प्लेटों में तकरीबन 1.00 लाख विलुप्त प्राय: प्रजातियों के साथ-साथ फायकस प्रजातियों के भी पौधे किसी भी ऋतु में पॉलीहाउस, मिस्ट चेम्बर व नेट हाउस की सहायता से तैयार किये जाते हैं।

जिनमें मुख्य रूप से बीज, अचार, हल्दू, कुल्लू, कुसुम, दहिमन, बेल, बरगद, पीपल, शीशम जैसे पौधे शामिल हैं। इस प्रकार से तैयार पौधे कालान्तर में सीधे ही रोपण हेतु व पोलीथीन में प्रतिरोपण हेतु स्वस्थ रूप से प्राप्त होते हैं।

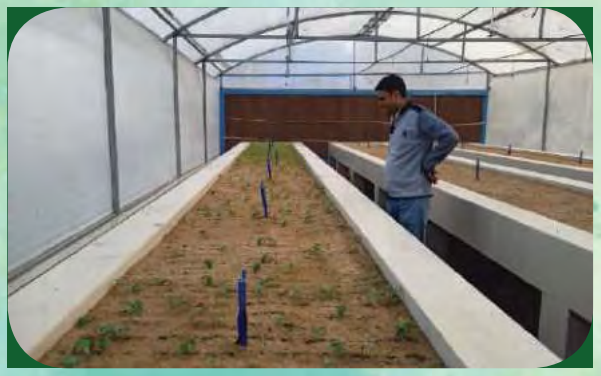

इस रोपणी में सागौन व बांस हेतु रूट स्टाक (जड़ भण्डार) रोपणी में ही अंकुरण अथवा मदर बेडों में तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत सागौन बीज का उपचारण रोपणी में ही कर मदर बेडों में बीजांकुरण का उन्नत किस्म के सागौन रूटशूट तैयार किये जाते हैं, जो कालान्तर में स्वस्थ पौधे के रूप में परिवर्तित हो सकें। साथ ही 0.50 लाख से 1.00 लाख बांस के पौधों हेतु राईजोम का उत्पादन भी इसी रोपणी से प्राप्त किया जाता है।

ग्रेडिंग शिफ्टिंग व पौधा रख-रखाव में लगातार नवाचार ने रोपणी को भव्यता प्रदान की है, व साथ ही बेहतर परिणाम भी परिलक्षित हुये हैं, जिससे पौधें के मजबूत तनों के साथ-साथ पौधों की वृद्धि में अनुकूलता पाई गयी है।

रोपणी में मुख्य रूप से सोलर संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करते हुये सौर ऊर्जा से माइक्रो स्प्रिंकलर जैसी उन्नत सिंचाई संसाधनों का उपयोग किया जाता है, व इन्हीं माइक्रो स्प्रिंकलर की सहायता से घुलनशील जैव उर्वरक को सिंचाई के माध्यम से पौधों तक पहुंचाकर उन्हें सुदृढ़ बनाया जाता है।

वर्मी कम्पोस्ट खाद के उत्पादन में भी रोपणी बांसापुर में उत्कृष्टता का परिचय देते हुये वर्ष 2021-22 में वन विभाग को 500 क्विंटल प्रदाय करते हुये स्वयं के उपयोग हेतु भी विगत वर्ष व इस वर्ष तैयार 15.00 लाख पौधा तैयारी हेतु वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार किया, जिस हेतु रोपणी के 20 पक्के बेडों व 25 HDEP bags की सहायता ली गई।

रोपणी बांसापुर में जहां विभिन्न अधोसंरचनाओं को उत्कृष्ट मानकों के साथ तैयार किया गया है, वहीं इन अधोसंरचाओं का रख-रखाव व उपयोग इस रोपणी को भव्यता प्रदान करता है।

Vulture Telemetry Project "Satellite Tracking of Vultures in Panna Tiger Reserve"

25 Vultures Tagged for Satellite-Tracking in Panna Tiger Reserve, A First in the Country

1. Introduction :

The exercise of capturing and GPS tagging of vultures in the wild, at Panna Tiger Reserve (PTR), in the central Indian state of Madhya Pradesh, is one among the first scientific undertakings of its kind, and the largest vulture telemetry projects in India. Current scientific literature shows fourteen vulture species have been tagged and studied across 24 countries, with none from India. Nine species of vultures are found in the country, of which three are critically endangered. Seven of these species are found in PTR. These include 3 migratory species namely, Himalayan Griffon (Gyps himalayensis), Eurasian Griffon (Gyps fulvus), and Cinereous vulture (Aegypius monachus), who migrate from Northern areas and come to PTR in the month of November and return back in the month of February-March. Four vulture species namely, Indian vulture (Gyps indicus), White-Rumped vulture (Gyps bengalensis), Red-headed vulture (Sarcogyps calvus) and Egyptian vulture (Nepphron percnopterus) are resident of PTR. Apart from the current telemetry study in PTR, being taken up as a part of Landscape Management Plan, telemetry projects are underway in the states of Himachal Pradesh and Gujarat, all of which are vital for science-based global conservation efforts, to prevent extinction of Old-World vultures in India.

2. Tagging Vultures at PTR :

The tagging is done with the help of Wildlife Institute of India (by a team of researchers and resource persons from Wildlife Institute of India and professional trappers) during the winters of 2020-2021 and 2021-2022. A total of 25 vultures have been tagged with solar GPS devices which includes 3D acceleration sensors and are being tracked through satellite transmission of data from the tags. This is perhaps the only large-scale telemetry study in India and the tagged birds include 13 Indian vultures, 02 Red-headed vultures (both are critically endangered), 08 Himalayan Griffons and 02 Eurasian Griffons (both are near threatened species).

Mechanism of the telemetry device deployed :

The Bird Solar UMTS tag, which has been used in the current telemetry study of the vulture in Panna Tiger Reserve, consists of a GPS sensor, solar charging panel, 3D acceleration sensor, two UMTS antennas, and one UHF antenna in it. The GPS sensor acquires the location of the individual, the 3D acceleration sensor records the movement pattern of the bird in the 3-dimensional axes. The battery, the primary power source of the tag, gets charged by the solar charging panel on the tag. The UMTS antenna transmits data or update the configuration of the tag through the mobile tower (GPRS/GSM based

connection). The UHF antenna gives the facility of the on-site tracking with the handheld terminal. Once deployed, the tag keeps logging the GPS location and 3D acceleration data of the individual bird which is kept stored in the storage device and gets transmitted periodically to a global data repository, Movebank. Once the data is transmitted, the tag removes the stored data. The user keeps downloading the data from the Movebank account associated with the current study. Since, bird like vulture moves for long distance daily and it is very difficult to track them on field due to rugged terrain, the UMTS tags give the opportunity to get the telemetry data with ease.

3. Movement Data of Migratory (Himalayan & Eurasian Griffon) and Resident Vultures:

(i) Update on movements of tagged Himalayan Griffons :

Movement of Himalayan Griffons for return journey from PTR started at the end of month of March. Movement data received on 27th April showed that 4 Himalayan Griffon vultures, with tag number HG_8673, HG_8677, HG_6987 and HG_8654 have crossed Indian border and were respectively in Tibetan region of China, Uyghur region of China near the Karakoram range, Nepal and Tibetan region of China. Later, data received on 9th May 2022, showed that HG_8677 had entered Kazakhstan crossing Kyrgyzstan and staying in Altyn Emel National Park, Kazakhstan. Daily average distance travelled was more than 100 km. Not all Griffons have taken the same route but the direction in which they are moving is same, Northwards. The route passes through Nepal and then enters China. Picture 1 shows the routes taken and location of HG_8673, HG_6987 and HG_8654 as on 27th April 2022:

Picture 1: Routes taken & Location of HG_8673, HG_6987 and HG_8654 as on 27th April 2022

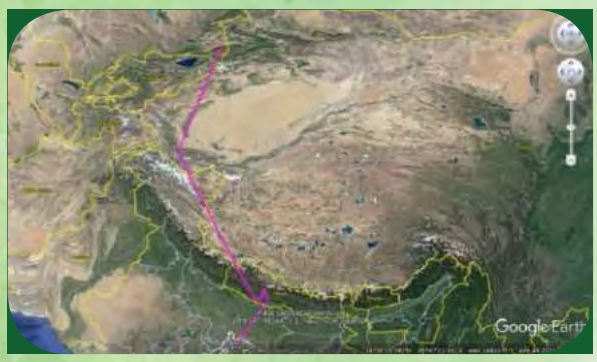

27th April, 2022

9th May, 2022

Picture 2 shows the routes taken and location of HG_8677 as on 27th April and 9th May, 2022:

(ii) Update of movements of tagged Eurasian Griffons :

The Eurasian Griffons started their journey back home later than Himalayan Griffons. Two Eurasian Griffon vultures were GPS tagged along with 23 other vultures and as per data received, these Eurasian Griffon started their return journey from PTR in the month of April. In the first week of May 2022, location of both the tagged Eurasian Griffons, EG_8643 and EG_8661, was in Pakistan. While EG_8643 was in Lal Suhanra National Park of Bhawalpur District of Punjab Province, Pakistan; the other Eurasian Griffon EG_8661 was in Shorkot Plantation Reserve near Multan district of Pakistan. EG_8661 first went to Pakistan in April and then came back all the way to MP and again went to Pakistan. Both the Eurasian Griffon vultures are further moving West. Picture 3 shows the routes taken and location of EG_8643 and EG_8661 as on 5th May 2022

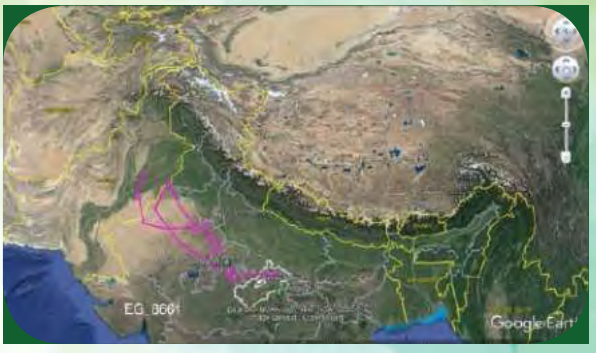

Picture3: Routes taken & Location of EG_8643 and EG_8661 as on 5th May, 2022

(iii) Update on movements of tagged resident vultures :

GPS tagged resident vultures namely, Indian Vultures and Red-headed vultures, mostly sub-adult, are showing very interesting behaviour. One Indian Vulture (IV_8671) travelled all the way to Bihar along the bank of the river Shone and came back and also visited Amarkantak-Achanakmar WLS. Two others Indian Vulture (IV_8670 & IV_8665) travelled up to Palpur-Kuno WLS in Sheopur district, and using Greater Panna Landscape

extensively. Picture 4 shows movements of IV_8671, IV_8670 and IV_8665 as on 27th April 2022.

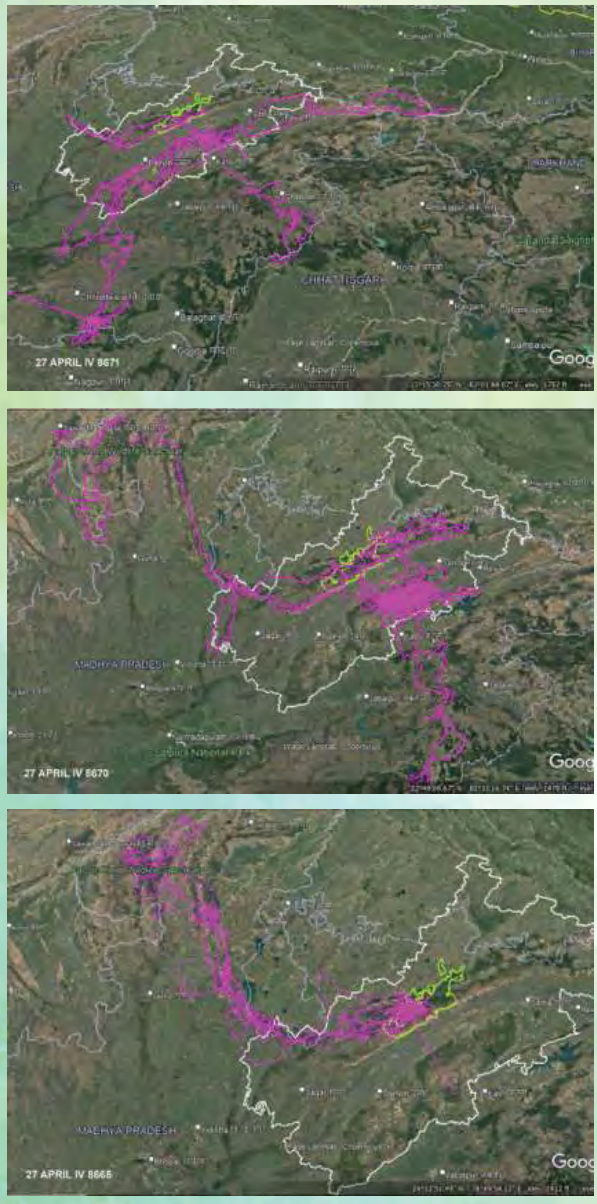

Picture 4: Movement of IV_8671, IV_8670 and IV_8665 as on 27th April 2022

The Red-headed Vultures are mostly confined within Greater Panna Landscape. Picture 5 shows the movement of one of the tagged Red-headed Vulture (RH_8660)

Picture 5: Movement of RH_8660 as on 27th April 2022

4. Conclusion :

Since the catastrophic decline of vultures over the end of the last century, telemetry-based research has become imperative for understanding movement patterns of these birds. This includes migration, foraging, roosting, nesting, bathing and other behaviours, understanding all of which is critical for their conservation, specifically when these birds require large area for survival including human spaces and carcass dumps. The current study will establish baseline data of these activities across a spatiotemporal scale. Furthermore, haematological, and microbiological analysis from the obtained samples will help determine the overall health status of the individuals and to a certain extent, about the health of vulture populations in and around the reserve. All findings from the current study will lead to significant policy implications, in providing answers to existing knowledge gaps, and towards adaptive management of these remarkable raptors in the Panna Landscape.

अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस-2022

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस (International Day for Biological Diversity)-22 के अवसर पर सी.बी.डी. द्वारा निर्धारित Building a shared future for all life विषय वस्तु पर श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के मुख्य आतिथ्य एवं श्री रमेश कुमार गुप्ता, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख की अध्यक्षता में 22 मई को आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा अकादमी, भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में मध्यप्रदेश, डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव, सदस्य सचिव, द्वारा मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा अवगत कराया कि अधिनियम एवं जैवविविधता नियम के प्रावधानों के अंतर्गत जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन, जैवसंसाधनों का संवहनीय उपयोग तथा लाभों का साम्यपूर्ण प्रभाजन के क्रियान्वयन हेतु जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन प्रावधानित है। प्रदेश में जैवविविधता अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय निकाय स्तर (पंचायत एवं नगरी निकाय) पर 23,557 जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। इसके साथ ही वन क्षेत्रों में लगभग 16,000 वन समितियों को भी जैवविविधता प्रबंधन समिति सह संयुक्त वन प्रबंधन समिति का दर्जा दिया गया है। बोर्ड द्वारा सेकेण्डरी डाटा के आधार पर समितियों के स्तर पर डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण किया गया है। इस डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी को बोर्ड द्वारा जैवविविधता से सरोकार रखने वाले विभागों, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों में पदस्थ जैवविविधता आधारित व्याख्याताओं तकनीकी सहयोग से व स्थानीय लोगों के परामर्श से लोक जैवविविधता पंजी को निरंतर अपडेट किया जा रहा है। लोक जैवविधिता पंजी में उपलब्ध जानकारी के आधार पर निकाय स्तर की कार्य योजना बना कर स्थानीय जैवविविधता एवं जैव संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जावे। इस कार्य में निकायों एवं समितियों को बोर्ड द्वारा मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

जैवविविधता अधिनियम, 2002 एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के मुख्य उद्देश्य- जैवविविधता संरक्षण, संवर्धन तथा जैव संसाधनों से उद्भूत लाभों का साम्यपूर्ण प्रभाजन है। इन उद्देश्यों को जमीनी स्तर तक क्रियान्वित किये जाने हेतु त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण किया गया है। जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर जैवविविधता प्राधिकरण, चेन्नई, प्रदेश स्तर पर राज्य जैवविविधता बोर्ड तथा स्थानीय निकाय स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियाँ हैं। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जैवविविधता प्रबंधन समितियों के सक्रियकरण हेतु वनमंडल के सहयोग से 300 वन परिक्षेत्र स्तर पर 600 मास्टर ट्रेनर चिन्हांकित किया गया है। प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर द्वारा मैदानी स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों के सक्रियकरण का कार्य किया जावेगा। प्रत्येक समिति स्तर पर उपलब्ध जैवविविधता एवं जैव संसाधनों तथा उससे संबद्ध पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण कार्य लोक जैवविविधता पंजी के रूप में किया जाना है। लोक जैवविविधता पंजी निर्माण तथा अद्यतनीकरण कार्य का दायित्व मुख्य रूप से जैवविविधता प्रबंधन समिति का है। बोर्ड द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन एवं कैम्पा मद अंतर्गत प्रदेश में 200 जनपद पंचायत, 9 नगर निगम, एवं 67 नगर पालिका स्तर पर लोक जैवविविधता पंजी का अद्यतनीकरण कार्य स्वीकृत किया गया है। इस क्रम में 40 जनपद पंचायत स्तर पर अद्यतनीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 एवं मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 22 के अनुसार जैवविविधता बाहुल्य क्षेत्र को जैवविविधता विरासत स्थल घोषित करने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत बोर्ड के तकनीकी सहयोग से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा निम्नानुसार जैवविविधता बाहुल्य क्षेत्र को जैवविविधता विरासत स्थल पातालकोट, जिला- छिंदवाड़ा, नरो हिल्स, जिला- सतना, अमरकंटक घोषित किया गया तथा जिला-अनूपपुर की प्रारूप अधिसूचना जारी की गयी। बोर्ड द्वारा Wildlife institute of india-WII Dehradun के

तकनीकी सहयोग से भोपाल एवं इंदौर का सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स (City Biodiversity Index) बनाने का कार्य प्रगति पर है। मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा जैवविविधता के प्रति जन जागरूकता हेतु प्रतिवर्ष/ समय-समय पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता ऑनलाइन क्विज-2021, श्रेष्ठ लोक जैवविविधता पंजी- 2021 पुरस्कार, जैवविविधता चित्रकला प्रतियोगिता- 2022 (03 श्रेणियों में), मध्यप्रदेश राज्य प्रवासी पक्षी ऑनलाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता - 2021 का आयोजन किया गया था।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के अवसर पर मुख्य अतिथि श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि जैवविविधता आज के परिप्रेक्ष्य में मानव जीवन के लिये आवश्यक घटक है। इसलिये इसका अस्तित्व बनाये रखना आवश्यक है। जैवविविधता संरक्षण हेतु जैवविविधता प्रबंधन समितियों की सक्रियता एवं जैवविविधता संस्थानीय समुदायों का भागीदारी आवश्यक है। इस हेतु बोर्ड द्वारा वन परिक्षेत्र स्तर पर तैयार किये जा रहे मास्टर ट्रेनर की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। बोर्ड द्वारा प्रदान किये जा रहे जैवविविधता पुरस्कार का उद्देश्य यही है कि आपके द्वारा जैवविविधता संरक्षण के क्षेत्र में किये गये प्रयास से समाज के अन्य व्यक्ति भी आप से इस पुनीत कार्य हेतु प्रेरित हो कर जैवविविधता संरक्षण में सहभागी बने। मध्यप्रदेश की वन संपदा, कृषि विविधता एवं नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण पारंपरिक ज्ञान के लिए विशिष्ट स्थान है। प्रदेश की जैवविधिता के जमीनी स्तर पर संरक्षण हेतु जैवविविधता अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय निकाय स्तर (पंचायत एवं नगरी निकाय) पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। जैवविविधता संरक्षण में स्थानीय निकाय में गठित जैवविविधता प्रबंधन समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। जैवविविधता प्रबंधन समितियों के सक्रियकरण की आवश्यकता है।

कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रमेश कुमार गुप्ता द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि वर्तमान में बढ़ती मानव जनसंख्या तथा मानव के स्वास्थ्य एवं उसकी आजीविका, भोजन खाद्य, पानी, दवाइयां हेतु इकोसिस्टम (पारिस्थितिकी तंत्र) पर निर्भरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज हमारे सभी ईकोसिस्टम पर अत्यधिक मानव दबाव है। सभी जीवन के लिये स्वच्छ एवं हरा-भरा पर्यावरण, पर्याप्त भोजन एवं स्वच्छ पानी एवं संवहनीय आजीविका के लिये हम सभी को संयुक्त प्रयास करना होगा। स्थानीय जैवविविधता का संरक्षण एवं पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण हेतु लोक जैवविविधता पंजी की गुणवत्ता बनाये रखने स्थानीय स्तर पर जैवविविधता से जुड़े व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त किया जावे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा जैवविविधता अधिनियम, 2002 एवं जैवविविधता अधिनियम के उदेश्यों के अनुरूप मध्यप्रदेश प्राकृतिक संरचना व संसाधनों, जैवविविधता व जैविक संसाधनों और जैव संसाधनों से संबद्ध पारंपरिक ज्ञान में संपन्न है। स्थानीय समुदाय के विकास के लिए जैवविविधता संरक्षण, जैविक संसाधनों के संवहनीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। लोक जैवविविधता पंजी के अद्यतनीकरण कार्य में पारम्परिक ज्ञान को अधिक से अधिक संकलित करें। जिससे कि पारम्परिक ज्ञान का संरक्षण एवं संवर्धन अधिक समय तक किया जा सके।

श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा प्रतिभागी को संबोधित करते हुये।

श्री रमेश कुमार गुप्ता, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा संबोधित करते हुये।

इस अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा ई-पुस्तक एवं जैवविविधता दिग्दर्शिका पुस्तक का विमोचन किया गया

जैवविविधता दिग्दर्शिका का अतिथियों द्वारा विमोचन

ई-बुक (फॉनल बायोडायवर्सिटी ऑफ मध्यप्रदेश) का विमोचन

श्री ए.के. पाटिल, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम, श्री पुष्कर सिंह, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघुवनोपज संघ, श्री जसबीर सिंह चौहान, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, मध्यप्रदेश, श्री सी.के. पाटिल, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (संरक्षण), डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल (म.प्र.), श्री सुनील अग्रवाल, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कैंपा), भोपाल (म.प्र.), श्री असीम श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन), भोपाल (म.प्र.), श्री राकेश कुमार यादव, प्रशासन मुख्य वनसंरक्षक (प्रशा.-1), भोपाल (म.प्र.), श्री पी.के. सिंह, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मानव संसाधन विकास), श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी), श्री अभिताभ अग्निहोत्री, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक/संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान, श्री असीम श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन) कार्यक्रम में उपस्थित हुए।

कार्यशाला में 10 जिलों के 12 वनमण्डलों के 38 वनपरिक्षेत्र द्वारा नामांकित मास्टर ट्रेनर (33, वनरक्षक- 28, स्थानीय रिसोर्स पर्सन, जैवविविधता प्रबंधन समिति के सदस्यगण-10) एवं महाविद्यालय तथा विद्यालय संस्थाओं के 32 पी.आई./को-पी.आई. (कुल-103 प्रतिभागी) उपस्थित रहे। इस अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता- मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता ऑनलाइन क्विज़- 2021 के 09 प्रतिभागी, जैवविविधता चित्रकला प्रतियोगिता- 16 प्रतिभागी, प्रवासी पक्षी ऑनलाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता- 06 प्रतिभागी, राज्य स्तरीय वार्षिक जैवविविधता पुरस्कार 2021 के 17 प्रतिभागी उपस्थित रहे।

अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस पर पुरस्कारों का वितरण

राज्य स्तरीय वार्षिक जैवविविधता पुरस्कार-2021

जैवविविधता संरक्षण को प्रोत्साहन देने एवं इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य कर रहे व्यक्ति, अशासकीय संस्थान, जैवविविधता स्वामित्व रखने वाले शासकीय विभागों (वन, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन एव जल संसाधन) को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय वार्षिक जैवविविधता पुरस्कार योजना वर्ष 2018 से प्रारंभ की गई है। यह पुरस्कार 06 विभिन्न श्रेणियों में प्रदाय किये जाते हैं। इन पुरस्कारों का वितरण प्रति वर्ष 22 मई को अन्तर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा आयोजित ''राज्य स्तरीय वार्षिक जैवविविधता पुरस्कार-2021" पुरस्कार वितरण कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस 22 मई को श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के मुख्य आतिथ्य एवं श्री रमेश कुमार गुप्ता, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र. की अध्यक्षता में आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में सम्पन्न हुआ।

''राज्य स्तरीय वार्षिक जैवविविधता पुरस्कार-2021" का श्रेणी जैवविविधता स्वामित्व रखने वाले विभाग (वन, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि में प्रथम पुरस्कार शहीद भीमा नायक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी एवं क्षेत्रीय वनमंडल, कटनी, श्रेणी - जैवविविधता प्रबंधन समिति, (स) नगर पालिका/नगर निगम में प्रथम- पुरस्कार राशि रु. 5.00 लाख जैवविविधता प्रबंधन समिति नगर पालिका महीदपुर उज्जैन, श्रेणी - संस्थागत (अशासकीय) में प्रथम पुरस्कार - राशि रु. 3.00 लाख सर्वहिताय संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था, नीमच, द्वितीय पुरस्कार राशि रु. 2.00 लाख मानस कान्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़ जिला धार, श्रेणी-व्यक्तिगत (अशासकीय) में प्रथम पुरस्कार - राशि रु. 3.00 लाख श्री राधेश्याम परिहार, आगर मालवा, द्वितीय पुरस्कार - राशि रू. 2.00 श्री एस.एल. गर्ग, इन्दौर, श्रेणी- व्यक्तिगत (शासकीय) में प्रथम पुरस्कार - राशि रु. 1.00 डॉ. अर्चना शुक्ला, शिक्षक, शासकीय एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल, सतना, द्वितीय पुरस्कार - राशि रु. 0.50 लाख, डॉ. गौरव कुमार सक्सेना, वनक्षेत्रपाल, वनपरिक्षेत्र बड़वारा, सामान्य वन मंडल कटनी, श्रेणी - पहुंच एवं लाभ प्रभाजन के अधिकतम अनुबंध (अ) श्रेष्ठ वनमंडल में क्षेत्रीय वनमंडल, कटनी, को प्रथम - पुरस्कार एवं द्वितीय पुरस्कार- क्षेत्रीय वनमंडल, सिंगरौली, श्रेणी (ब) श्रेष्ठ वन वृत्त, अंतर्गत प्रथम पुरस्कार वन वृत्त, जबलपुर तथा द्वितीय पुरस्कार, वन वृत्त रीवा - को प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान किया गया। श्रेणी- पहुंच एवं लाभ प्रभाजन की अधिकतम राशि (अ) श्रेष्ठ वनमंडल अंतर्गत प्रथम पुरस्कार- क्षेत्रीय वनमंडल, कटनी एवं द्वितीय पुरस्कार-क्षेत्रीय वनमंडल, सिंगरौली, श्रेणी- (ब) श्रेष्ठ वन वृत्त अंतर्गत प्रथम पुरस्कार- वन वृत्त जबलपुर एवं द्वितीय पुरस्कार वन वृत्त रीवा को प्रदान किया गया।

प्रथम पुरस्कार - शहीद भीमा नायक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी

प्रथम पुरस्कार - क्षेत्रीय वनमंडल, कटनी

प्रथम पुरस्कार - जैवविविधता प्रबंधन समिति
नगर पालिका महीदपुर, उज्जैन

प्रथम पुरस्कार - सर्वहिताय संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था, नीमच

द्वितीय पुरस्कार - मानस कान्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़ जिला धार

प्रथम पुरस्कार - श्री राधेश्याम परिहार, आगर मालवा

द्वितीय पुरस्कार - श्री एस.एल. गर्ग, इन्दौर

प्रथम पुरस्कार - डॉ. अर्चना शुक्ला, शिक्षक, शासकीय एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल, सतना

द्वितीय पुरस्कार - डॉ. गौरव कुमार सक्सेना, वन क्षेत्रपाल, वनपरिक्षेत्र बडवारा, सामान्य वनमंडल, कटनी

वार्षिक जैवविविधता पुरस्कार के विजेतागण

श्रेष्ठ लोक जैवविविधता पंजी अद्यतनीकरण पुरस्कार - 2022

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल द्वारा प्रदेश में स्थानीय निकाय- ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा नगरीय निकाय- नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत गठित जैवविविधता प्रबंधन समिति स्तर पर लोक जैवविविधता पंजी का अद्यतनीकरण कार्य (एक वर्ष की समयावधि में) वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 की अवधि में शैक्षिणिक संस्थाओं (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय) को स्वीकृत किया गया था। बोर्ड द्वारा मूल्यांकन के आधार पर श्रेष्ठ लोक जैवविविधता पंजी अद्यतनीकरण का प्रथम पुरस्कार- जनपद पंचायत टिमरनी, जिला-हरदा, द्वितीय पुरस्कार- जनपद पंचायत सिहोरा एवं मझौली, जिला-जबलपुर एवं तृतीय पुरस्कार- जनपद पंचायत बनखेड़ी, जिला-नर्मदापुरम् को प्रदान किया गया।

श्रेष्ठ लोक जैवविविधता पंजी अद्यतनीकरण के पुरस्कार विजेतागण

अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी

बोर्ड द्वारा जैवविविधता प्रबंधन समितियों के सहयोग से प्रदेश की जैवविविधता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।

जैवविविधता प्रबंधन समितियों के सहयोग से प्रदर्शित प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुये श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

वनांचल संदेश पत्रिका माह “अक्टूबर - दिसम्बर 2021” का विमोचन

प्रदेश में वन विभाग द्वारा वनों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में प्रभावी पहल हुई है, जिसका लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। वन संसाधनों से समृद्ध मध्यप्रदेश में वन, वन्यजीव एवम् वनवासी एक-दूसरे के परिपूरक हैं। वानिकी विकास एवम् विस्तार से वनवासी कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। प्रदेश में जन-भागीदारी के द्वारा वानिकी गतिविधियों के क्रियान्वयन से वानिकी विकास एवम् संवर्धन के बेहतर परिणाम मिले हैं, इस दिशा में विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों को वनांचल संदेश के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है।

विभागीय पत्रिका वनांचल संदेश का प्रकाशन त्रैमासिक रूप में किया जा रहा है। इस पत्रिका के माध्यम से विगत तिमाही में वन विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है। विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों एवं समितियों के उत्कृष्ट कार्य/सफलता की कहानी पत्रिका में विशेष रूप से आकर्षण का केन्द्र रहती हैं।

वनांचल संदेश पत्रिका माह ”अक्टूबर - दिसम्बर 2021” का विमोचन माननीय वन मंत्री डॉ. कुँवर विजय शाह द्वारा किया गया। इस अवसर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री रमेश कुमार गुप्ता, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अनु.वि. एवं लोकवानिकी श्री अतुल कुमार जैन,प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव एवं अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अनु.वि. एवं लोकवानिकी डॉ. यू. के. सुबुद्धि उपस्थित रहे।

क्या आप जानते हैं ?

1) मध्यप्रदेश में सर्वप्रथम सिवनी जिले के देरेशी एवं डुगरताल क्षेत्र को आरक्षित वन के रूप में 1832 के राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया था। यह किसी नियम एवं अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किये थे। यह आरक्षित क्षेत्र लगभग 120 वर्गमील में फैला था वर्ष 1850 में सागौन वृक्षों के पातन के संबंध में प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई थी। भारतीय वन अधिनियम, 1863 तथा वेस्ट लैण्ड लीज रूल्स 1863 के अंतर्गत किया जाता था। वर्तमान देरेशी एवं डुगरताल वन क्षेत्र दक्षिण सिवनी वनमंडल के अंतर्गत आते हैं।

2) भारत में रेल के विस्तारीकरण के लिये काफी मात्रा मे स्लीपर की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये मण्डला जिले के सागौन वृक्षों का पातन किया जाकर नर्मदा नदी में राप्ट के माध्यम से जबलपुर भेजे जाते थे। जबलपुर में नर्मदा नदी के ग्वारी घाट पर स्लीपर का संग्रहण किया जाता था, जिसके लिये ग्वारी घाट पर वर्ष 1860 में एक कस्टम हाउस की स्थापना की गई थी। ग्वारी घाट कस्टम हाउस पर 1 आना प्रति घनफुट की दर से शुल्क वसूला जाता था, जिससे प्रति वर्ष 13000/- रुपये की आमदनी होती थी।

3) वन प्रशासन का सर्वप्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1860-61 में प्रकाशित किया गया था। यह प्रशासनिक प्रतिवेदन मुख्यत: सागर एवं नर्मदा (वर्तमान जबलपुर) क्षेत्रों के वन विस्तार एवं भविष्य के लिये आरक्षित वन बनाने के सर्वेक्षण से संबंधित था। वर्ष 1862-63 तक प्रशासनिक प्रतिवेदन वनों के विस्तार एवं आरक्षित किये जाने एवं व्यय एवं राजस्व के संबंध में होते थे। वर्ष 1864 में तत्कालीन मुख्य वनसंरक्षक, डी. ब्रानडिश (बाद में आई.जी. फारेस्ट नियुक्त हुये) के सुझाव के पश्चात् प्रशासनिक प्रतिवेदन में अनेक परिवर्तन किये गये।

4) छिंदवाड़ा जिले में देनवा में स्थित साल वन पचमढ़ी के ठाकुर परिवार के अधीन थे। इन वनों में स्लीपर प्राप्त करने के लिये पचमढ़ी के ठाकुर एवं वन अधीक्षक/उप आयुक्त छिंदवाड़ा के मध्य दिनांक 13 नवम्बर 1862 को एक अनुबंध किया गया जिसके अनुसार वनों से साल की लकड़ी कटाई का कार्य शासन द्वारा किया जायेगा तथा इससे प्राप्त हाने वाली आय पचमढ़ी के ठाकुर परिवार को दी जायेगी।

5) होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले बोरी आरक्षित वनों का गठन सन् 1862 में किया गया था, जिसे वैद्यानिक रूप से आरक्षित वन भारतीय वन अधिनियम, 1865 के अन्तर्गत वर्ष 1865 में अधिसूचित कर प्रदाय किया गया। आरक्षित वन गठित होने से बोरी वन पचमढ़ी के कोरकू जमींदार ठाकुर भाभूतसिंह के आधिपत्य में था, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा राससात किया था। बोरी वनक्षेत्र में सन् 1864 से अग्नि सुरक्षा का कार्य किया जा रहा है। इस क्षेत्र में वर्ष 1870 में प्रथम वृक्षारोपण किया गया था। बोरी आरक्षित वन की प्रथम कार्य-आयेजना वर्ष 1897 में अनुमोदित की गई थी।

कभी सागौन लेकर के....!

ये जो लकड़ी के तस्कर हैं बड़े निर्मम निकलते हैं.
कभी सागौन लेकर के, कभी शीशम निकलते हैं.

न इनका वक्त आने का, न इनका वक्त जाने का,
कुठाराघात करने को ये हर मौसम निकलते हैं.

सिपाही वन का रहता है हमेशा मुर्दनी ओढ़े,
ये हथियारों के बलबूते पे ताज़ादम निकलते हैं.

ये रहते सरपरस्ती में हमेशा ही सियासत की,
तभी हम्माम तक में भी बिछे जाज़म निकलते हैं.

अगर मुठभेड़ होती है तो मरता है सदा ख़ाकी,
न घर से और दफ्तर से बड़े हाक़िम निकलते हैं.

यहाँ पौधों के रोपण में है ये ख़ूबी यहाँ गड्ढे ,
लगे पौधों की तुलना में हमेशा कम निकलते हैं.

मदद सरकार की मिलती तो मिलती है इसी सूरत,
इधर जब ज़ख्म सूखे हैं उधर मरहम निकलते हैं.

पकड़ जाये कहीं कोई किसी अपराध में तो फिर,
सियासी दल बचाने को लिए परचम निकलते हैं.

अधीनस्थों की सुविधाओं की जब भी बात चलती है,
नियम में, क़ायदों में तब हजारों ख़म निकलते हैं.

रत्नदीप खरे
मोबा. 98260 43425

भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति

भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति (जनवरी-जून 2022)

Alok Kumar
P.C.C.F. (Wildlife)

Pankaj Shrivastava
P.C.C.F.(I.I.F.M., Bhopal)

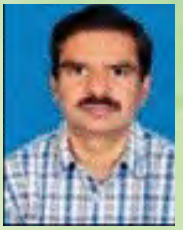

Dr. Dharmendra Verma
P.C.C.F. (Training) H.O. Bhopal & Member Secy., Bio-Diversity, Bhopal

Rajesh Kumar
P.C.C.F. (Working Plan & FLR)

Lal Singh Rawat
A.P.C.C.F.(Co-ordination) H.Q. Bhopal

K. Raman
A.P.C.C.F. Green India Mission H.Q. Bhopal

Ram Dass Mahala
A.P.C.C.F. Jabalpur Circle

Himmat Singh Negi
A.P.C.C.F. (W.L.) H.Q. Bhopal

Mahendra Singh Sisodia
C.C.F. Khandwa Cirlce

Jam Singh Bhargav
D.F.O. Shajapur (T) Division

Hari Shankar Manjhi
D.F.O. Rajgarh (T) Division

भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति (जनवरी-जून 2022)

Chitranjan Tyagi
P.C.C.F. (Development)
H.Q. Bhopal

Dr. Atul Kumar Srivastava
P.C.C.F., (Working Plan & FLR), H.Q. Bhopal

राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पदोन्नत अधिकारियों की सूची (जनवरी-जून 2022)		
श्री अनिल चौपड़ा	उप वनसंरक्षक/मंडल प्रबंधक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम, उमरिया (प्रतिनियुक्ति पर)	उप वनसंरक्षक/मंडल प्रबंधक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम, उमरिया (प्रतिनियुक्ति पर)
श्री सुखलाल भार्गव	प्रभारी वनमण्डल अधिकारी, बड़वानी (सामान्य) वनमण्डल	वनमण्डल अधिकारी, बड़वानी (सामान्य) वनमण्डल
श्री ध्यान सिंह निगवाल	प्रभारी वनमण्डल अधिकारी, उत्तर बालाघाट (उत्पादन)	वनमण्डल अधिकारी, उत्तर बालाघाट (उत्पादन)
श्री संदीप फैलोज	उप वनसंरक्षक म.प्र. राज्य वन विकास निगम, सीधी (प्रतिनियुक्ति पर)	उप संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, होशंगाबाद
श्री व्ही. सी. मेश्राम	उप वनसंरक्षक/मंडल प्रबंधक, म.प्र.राज्य वन विकास निगम, सिवनी (प्रतिनियुक्ति पर)	वनमण्डल अधिकारी, डिण्डोरी (उत्पादन) वनमण्डल (प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए)
श्री डी. के. वासनिक	उप वनसंरक्षक/मंडल प्रबंधक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम, विदिशा-रायसेन (प्रतिनियुक्ति पर)	वनमण्डल अधिकारी होशंगाबाद (सामान्य) वनमण्डल (प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए)
श्री हेमंत कुमार रायकवार	प्रभारी वनमण्डल अधिकारी, बड़वानी (सामान्य) वनमण्डल	वनमण्डल अधिकारी, गुना (सामान्य) वनमण्डल
श्री सुदेश महिपाल	उप वनसंरक्षक/मंडल प्रबंधक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम, बालाघाट (प्रतिनियुक्ति पर)	वनमण्डल अधिकारी, डिण्डोरी (उत्पादन) वनमण्डल (प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए)
श्री हरे सिंह ठाकुर	उप बनसंरक्षक/मंडल प्रबंधक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम, बालाघाट (प्रतिनियुक्ति पर)	वनमण्डल अधिकारी, झाबुआ (सामान्य) वनमण्डल

श्री गरीब दास बरखड़े	प्रभारी वनमण्डल अधिकारी, डिण्डोरी (उत्पादन) वनमण्डल	वनमण्डल अधिकारी, धार (सामान्य) वनमण्डल
श्री मगन सिंह डाबर	उप वनमण्डल अधिकारी बिस्टान (सामान्य) वनमण्डल खरगौन	उप वनसंरक्षक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम, भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर)
श्रीमती भारती ठाकरे	सहायक संचालक (सिवनी क्षेत्र) पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी	उप वनसंरक्षक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम, भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर)
श्री रमेश राठौर	सहायक वनसंरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख, भोपाल	उप वनसंरक्षक, म. प्र. ईको पर्यटन विकास, भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर)
श्री शिव करण अटोदे	अधीक्षक, गांधीसागर अभ्यारण्य, मंदसौर (सामान्य) वनमण्डल	वनमण्डल अधिकारी, रायसेन (उत्पादन) वनमण्डल (प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए)
श्री लक्ष्मीकांत वासनिक	उप वनमण्डल अधिकारी, सिवनी (सामान्य), दक्षिण सिवनी (सामान्य) वनमण्डल	वनमण्डल अधिकारी, छिंदवाड़ा (सामान्य) वनमण्डल
श्री रितेश सरोठिया	प्रभारी टाइगर स्ट्राइक फोर्स, (वन्य प्राणी) मुख्यालय भोपाल	उप वनसंरक्षक (वन्य प्राणी) मुख्यालय भोपाल
श्री रजनीश कुमार सिंह	सहायक वनसंरक्षक (वन्य प्राणी) मुख्यालय भोपाल	उप संचालक पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी
सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे	उप वनमण्डल अधिकारी, (मानपुर) बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया	वनमण्डल अधिकारी, खण्डवा (उत्पादन) वनमण्डल
श्री अशोक कुमार सोलंकी	उप वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण हरदा (सामान्य), हरदा (सामान्य) वनमण्डल	वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण शहडोल (सामान्य), वनमण्डल
श्रीमती प्रतिभा अहिवार	सहायक वनसंरक्षक, टाइगर स्ट्राइक फोर्स, इन्दौर	उप वनसंरक्षक म.प्र. राज्य वन विकास निगम, भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर)
श्री राकेश कुमार डामर	उप वनमण्डल अधिकारी पूर्व कालीभीत (सामान्य), खण्डवा (सामान्य), वनमण्डल	वनमण्डल अधिकारी, उत्तर बैतूल (सामान्य), वनमण्डल

वनिकी गतिविधियां कार्टूनिस्ट की नजर में

अखबारों के आईने में

दैनिक जागरण भोपाल

21 FEB 2022

एक से पांच मार्च तक पौधारोपण महाअभियान

जागरण, सीहोर। पौधारोपण को जन आन्दोलन बनाने के लिए मुख्यमंत्री के संकल्प को जन भागीदारी से एक महाअभियान का रूप दिया जा रहा है। नागरिकों समुदायों, शासकीय विभाग एवं स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से एक मार्च से 5 मार्च 2022 तक अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण का अभियान चलाया जाए। पाँच मार्च, 2022 को राज्य एवं जिला स्तरीय समारोह में पर्यावरण विभाग द्वारा संचालित अंकुर कार्यक्रम अन्तर्गत प्राणवायु अवार्ड प्रदान किये जाएंगे। कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने इस अभियान को पूरी गंभीरता से संचालित करने सभी संबंधित अधिकारियों को राज्य शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

बंसी एंपोरियम में महिलाओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण

महिलाएं सीख रहीं बांस से डलिया, टोकरी दीवार घड़ी, लैप और स्टूल बनाना

Page 2

बाघों के बाद मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या भी बढ़ने के आसार

अपनी खबर

शुरू होगा औषधीय प्रसंस्करण, बनेगी दवाइयां

मुकुंदपुर सफारी में 8500 वर्गमीटर में बनेगा तितली पार्क

52 प्रजाति की तितलियां

तितलियों के बटेंगे सेक्टर

अखबारों के आईने में

Page 2

इकोलॉजिकल पार्क में वन विभाग का अभियान...

महाभारतकालीन शल्यकर्णी समेत 18 विलुप्त प्रजातियों के पौधे रोपे

सिटी रिपोर्टर | भोपाल

पहल • धार्मिक-सार्वजनिक स्थान और घरों में पौधे लगाने वन विभाग की अनूठी मुहिम

पौधे लगाओ और तीर्थों जैसा पुण्य कमाओ... घर की वाटिका में दिव्य पौधे लगाएं, अपनों को उपहार में भी दें

सिटी रिपोर्टर | भोपाल

सार्वजनिक जगह पर पौधे लगाकर ले सकते है लाभ

हर पौधे के लिए दिशा निर्धारित

सभी पौधे धर्मशास्त्र सम्मत

12 सिटी स्टार

एक जिला-एक उत्पाद योजना के तहत बांस रोपण की हुई कार्यशाला

पांच से दस हजार एकड़ क्षेत्र में हो सकती है बांस की खेती : वर्णवाल

छात्रावास के निरीक्षण में मिली गंदगी, लगाई फटकार

मुंबई, बनारस औद्योगिक कॉरिडोर का भाग है रीवा

सामुदायिक वन प्रबंधन को लेकर कार्यशाला आयोजित

Devraj Dharmik

Published by:-APCCF (R/E) on behalf of MP Forest Department.
Printed by:-Super Printers & Plastics Works on behalf of Madhya Pradesh Madhyam.
Printed at :- Super Printers & Plastics Works, Plot No. 22 Nadeem House, Press Complex Zone 1, M P Nagar, Bhopal
Published at Room No. 140, Prachar Prasar Prakosth, Satpura Bhavan, Bhopal, M.P
Email:-dcfpracharprasar@mp.gov.in, Contact No. 0755-2524293, Editor:-Sanjay shukla, APPCF (R/E)